कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

माघ–फाल्गुन 2081, फरवरी 2025

केंद्रीय बजट 2025-26

चुनौतियों के बीच विवेकपूर्ण बजट

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

पूर्वी उड़ीसा

राजकोट, सौराष्ट्र

वीर नर्मद, गुजरात (दक्षिण)

स्वदेशी शोध संस्थान, दिल्ली

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–33, अंक–2
माघ–फाल्गुन 2081 फरवरी 2025

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

केंद्रीय बजट 2025–26
चुनौतियों के बीच विवेकपूर्ण बजट
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 बजट समीक्षा
भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला बजट
अनिल तिवारी

10 बजट समीक्षा
केंद्रीय अर्थ संकल्प 2025–26 : निशाने पर तीर
अनिल जवलेकर

12 बजट समीक्षा
वित्तीय वर्ष 2025–26 का अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट
प्रहलाद सबनानी

14 बजट समीक्षा
एमएसएमई को बढ़ावा एवं युवाओं को रोजगार देने वाला बजट
डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा

16 बजट समीक्षा
दुनिया भर में बढ़ रहा है रक्षा का बजट
गणेश गौतम

18 विश्व रेडियो दिवस
डिजिटल होती दुनिया में भी बरकरार है रेडियो का जादू
शिवनंदन लाल

20 पर्यटन
पर्यटन के विस्तार से अर्थव्यवस्था को मजबूती
डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

22 बहस
क्या भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा
स्वदेशी संवाद

25 महाकुंभ
अद्भुत अलौकिक अपूर्व – महाकुंभ
विनोद जौहरी

27 विश्व आद्रभूमि दिवस
साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण आवश्यक
सुशील कुमार महला

30 मुद्दा
उपग्रह प्रक्षेपण से बढ़ता प्रदूषण
विजय गर्ग

32 समीक्षा
गंगा का विज्ञानः प्राचीन ज्ञान और आधुनिक खोज का संगम
सचिन अवस्थी

34 दिव्य विभूतियां
'मन चंगा तो कठौती में गंगा': संत रविदास
हेमेन्द्र क्षीरसागर

पाठकनामा

केंद्रीय बजट 2025–26 में सबको राहत

वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025–26 आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए सरकार की दूरदृष्टि का प्रतीक है। 10 लाख करोड़ रूपये के बुनियादी ढांचा विकास के आवंटन के माध्यम से, बजट आर्थिक विकास को प्रोत्साहित, रोजगार के अवसर पैदा करना और नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, जिसमें कर छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जो उपभोक्ता खर्च और समग्र मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विवेकपूर्ण कदम है। इस उपाय का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवारों से अपने उपभोग व्यय को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वहीं 10,000 करोड़ रूपये के फंड के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और उन्हें आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करने से वे विकसित, नवाचार और रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे।

शिक्षा के लिए 1.5 लाख करोड़ रूपये और स्वास्थ्य सेवा के लिए 1.2 लाख करोड़ रूपये का बजट आवंटन भी उल्लेखनीय है। 20,000 करोड़ रूपये के फंड के माध्यम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर बजट का जोर सतत् विकास के महत्व को दर्शाता है। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025 भारत के आर्थिक विकास और विकास के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बुनियादी ढांचा विकास, कर राहत, एमएसएमई समर्थन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता देकर, बजट भारत के निरंतर विकास और समृद्धि की नींव रखता है।

विजीत कुमार, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

मानव तस्करी में लगे गिरोह गरीब घरों के बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, उन्हें तरह–तरह के सपने दिखा प्रलोभन देते हुए झूठे वादे करते हैं। इसलिए हमें पूरे मानव तस्करी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ लड़ने की जरूरत है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

हम दशकों से वैश्वीकरण की बात करते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया विभिन्न मुद्दों पर टुकड़ों में बंटती दिख रही है।

निर्मला सीतारमण
वित्तमंत्री, भारत

हम सभी जानते हैं कि कृषि के बाद कपड़ा क्षेत्र हमारे देश में सबसे बड़ा रोजगार निर्माता है। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में नौकरियों की संख्या 45 मिलियन से बढ़ाकर 60 मिलियन करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय बजट में इस सेक्टर को 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

गिरिराज सिंह
कपड़ा मंत्री, भारत

संपादकीय

समाप्त हो रही है मुक्त व्यापार की प्रासंगिकता

अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों से आयात पर उच्च टैरिफ (जवाबी आधार पर) लगाने की अपनी मंशा की घोषणा करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक मुक्त व्यापार प्रणाली पर सीधा हमला बोल दिया है। 1990 के दशक से, एक दृष्टिकोण जोर पकड़ रहा था कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति ही दुनिया के लिए, खासकर विकासशील देशों के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'टैरिफ युद्ध' की घोषणा के साथ परिदृश्य अचानक बदल गया है। यह उल्लेखनीय है कि यह अमेरिका और उसके सहयोगी ही थे जिन्होंने दुनिया को मुक्त व्यापार की ओर धकेला था, खासकर विश्व व्यापार संगठन के गठन के साथ, जिसने नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली की शुरुआत की। विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के साथ, टैरिफ धीरे–धीरे कम हो गए और गैर–टैरिफ बाधाओं की संख्या और तीव्रता भी कम हो गई। मुक्त व्यापार के समर्थक व्यापार नीति पर चर्चा में हावी हो गए, क्योंकि वे विश्व व्यापार संगठन के बाद के दौर में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भरोसा कर रहे थे, जिसने उनके अनुसार विकासशील देशों को उच्च विकास दर हासिल करने में मदद की थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन व्यापार प्रणाली की अवहेलना शुरू की। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान पैनलों के न्यायाधीशों के नामांकन को अवरुद्ध कर दिया। इसने विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान तंत्र को लगभग पंगु बना दिया, जो नियम आधारित व्यापार प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। अब अपने दूसरे कार्यकाल में, डोनाल्ड ट्रम्प एकतरफा टैरिफ तय करके विश्व व्यापार संगठन के मूल नियम को ही पलट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क बहुत सरल है कि यदि अन्य देश अमेरिकी निर्यात पर उच्च टैरिफ लगा रहे हैं, तो अमेरिका भी उच्च टैरिफ लगाएगा, जिसे वे जवाबी टैरिफ कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्रवाई से विश्व अब उच्च टैरिफ की ओर आगे बढ़ेगा। यह डब्ल्यूटीओ व्यापार प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

हालांकि, देखने में, ट्रंप का तर्क वैध लगता है, कि वे जवाबी आधार पर उच्च टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि अन्य देश अमेरिकी निर्यात पर उच्च टैरिफ लगा रहे हैं; लेकिन वास्तव में, ऐसा नहीं है। 1987–88 में गैट वार्ताओं में जो नए मुद्दे जोड़े गए, उनमें मुख्य रूप से ट्रिप्स (व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार), ट्रिम्स (व्यापार संबंधी निवेश उपाय), कृषि और सेवा समझौते शामिल थे। विकासशील देश नए मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे स्वास्थ्य सुरक्षा, घरेलू उद्योग, कृषि और सबसे बढ़कर संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले थे; और वे वास्तव में विकसित देशों के पक्ष में डिजाइन किए गए थे। यह वह समय भी था जब भारत और अन्य विकासशील देश अपने–अपने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए उच्च टैरिफ लगा रहे थे; और गैर–टैरिफ बाधाएं भी लगा रहे थे। सौदे को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, विकासशील देशों को गैट में नए मुद्दों को स्वीकार करते हुए ट्रिप्स, ट्रिम्स, कृषि और सेवाओं पर समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए विकसित देशों की तुलना में उच्च टैरिफ लगाने की छूट की पेशकश की गई थी। डब्ल्यूटीओ प्रणाली से अमेरिका और अन्य विकसित देशों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि इसने मजबूत पेटेंट व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे उनकी फार्मा और अन्य कंपनियों को ज़्यादा रॉयल्टी मिलने लगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के लिए विकासशील देशों के दरवाजे खुले और भारत सहित अन्य विकासशील देशों में अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए बाजार खुल गए। लेकिन विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश के बाद उसकी आक्रामक विदेश व्यापार नीति ने न केवल भारत बल्कि अमेरिका और यूरोप के विनिर्माण को भी बहुत बड़ा झटका दिया। इतना ही नहीं, अपने विशाल व्यापार अधिशेष और तीव्र विकास के कारण चीन की बढ़ती सामरिक शक्ति ने अमेरिका की ताकत को चुनौती देनी शुरू कर दी। जो लोग 1990 के दशक से अमेरिका के दबाव में अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति के प्रबल समर्थक थे, वे अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण स्तब्ध हैं। भारत के वे सभी विशेषज्ञ जो मुक्त व्यापार के लाभों का बखान करते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब अन्य देश भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और आयात शुल्क में और वृद्धि करेंगे, तो वे उन्हें गलत कैसे साबित कर पाएंगे।

यह समझना होगा कि आर्थिक सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर काम करते हैं; और यदि वे मान्यताएं अब सत्य नहीं हैं, तो हमें ट्रैक बदलने की आवश्यकता होती है। यह बात मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर भी लागू होती है। यदि मुक्त व्यापार नीतियों को अपनाने के कारण भारत और अन्य देशों में विनिर्माण में गिरावट आई, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी, और विदेशों पर निर्भरता बढ़ गई, तो नीतियों में उचित बदलाव लाने की आवश्यकता है। पिछले करीब पांच वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भर भारत की नीति के माध्यम से देश में उन सभी वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिनमें उसकी चीन समेत अन्य देशों पर निर्भरता थी। इस नीति ने परिणाम भी देने शुरू कर दिए हैं। इस नीति की सफलता में सबसे बड़ी बाधा यह है कि अभी हमारे आयात शुल्क बहुत कम हैं। अगर आत्मनिर्भर भारत नीति को सफल होना है तो चीन से आयात बंद करना होगा। यह समझने की जरूरत है कि अतीत में मुक्त व्यापार के सबसे बड़े पैरोकार, उदाहरण के लिए अमेरिका, अब अपने–अपने देशों के हित में संरक्षणवादी बन रहा है। इसलिए अमेरिका के जवाबी शुल्क के बाद मुक्त व्यापार नीतियां प्रासंगिक नहीं रह जाएंगी। आज जब मुक्त व्यापार के सबसे बड़े साधन विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं, तब मुक्त व्यापार की वकालत करने का कोई औचित्य नहीं है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना होगा तथा सुरक्षात्मक वातावरण में अपने उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा।

केंद्रीय बजट 2025–26

चुनौतियों के बीच विवेकपूर्ण बजट

जबकि पिछली दो तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि में मंदी, रुपये में गिरावट, लगातार मुद्रास्फीति, खपत में कमी, बढ़ता व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं, सरकार के लिए विनिर्माण वृद्धि, कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, किसानों का समर्थन और कृषि उत्पादन में असंतुलन को दूर करना, दालों और खाद्य तेलों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम करना, मध्यम आय वाले करदाताओं को कर में राहत देना और साथ ही मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को दूर करना वास्तविक चुनौती थी। बजट 2025–26 ने इन सभी चिंताओं को संतुलित करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

लेकिन, यह भी सही है कि तमाम बाधाओं के बावजूद, देश की राजकोषीय सेहत काफी अच्छी स्थिति में थी। कम राजकोषीय घाटा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों में उछाल, भारी मात्रा में एनआरआई प्रेषण और चालू वित्त वर्ष में निवेश की घोषणाओं में वृद्धि वित्त मंत्री के काम को आसान बना रही थी। इससे वित्त मंत्री को छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विनिर्माण के लिए अधिक प्रावधान करने के अलावा बड़े पूंजीगत व्यय जारी रखने की गुंजाइश मिल सकी।

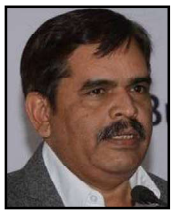

इस बजट में ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले गिग वर्करों को मान्यता देने, उन्हें ई–श्रम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने और उन्हें स्वास्थ्य कवर का लाभ देने के अलावा श्रम गहन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का काम किया गया है। लंबे समय से ***भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच*** *गिग वर्करों के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग कर रहे थे।*
– डॉ. अश्वनी महाजन

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार आयकर के मामले में मध्यम वर्ग को कुछ राहत पहले से भी दे रही थी, लेकिन कहानी यह रही है कि हर बजट में मध्यम वर्ग को बहुत कम लाभ मिलता है। लेकिन मोदी 3.0 में अपने पहले पूर्ण बजट में, वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को, 12 लाख रुपये की वार्षिक आय या एक लाख रुपये की मासिक आय तक किसी भी कर का भुगतान करने से मुक्त करके वास्तव में बड़ी राहत दी है। वेतनभोगी वर्ग के मामले में, यह छूट 12.75 लाख है, क्योंकि उन्हें अपनी आय से 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलता है। हालांकि, 12 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोग उतने भाग्यशाली नहीं हैं, लेकिन हालांकि, एक लाख रुपये मासिक आय वाले लोगों जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन उन्हें भी कुछ राहत जरूर मिली है,।

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

आत्मनिर्भर भारत नीति की शुरुआत के बाद से, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट 2025–26 में विनिर्माण को बढ़ावा देने का विशेष प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और मोटर, पवन ऊर्जा उपकरण और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण शामिल हैं। एमएसएमई विनिर्माण मिशन, एमएसएमई के लिए बढ़ी हुई ऋण गारंटी; उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड; पहले की सूची से आगे पीएलआई योजना का विस्तार; और देश को चीनी प्रभुत्व से बचाने के लिए विनिर्माण में सुधार के लिए कई अन्य उपाय इस बजट की महत्वपूर्ण पहल हैं। सरकार का वर्तमान प्रयास भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक वृहत कार्य करेगा, और वह भी एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से।

इस बजट में लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और अन्य स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वच्छ तकनीक मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयातित बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और सौर सेल के लिए विदेशों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण हमारा आयात बिल बढ़ रहा है और भविष्य में आयातित घटकों पर हमारी निर्भरता के कारण देश का शोषण भी हो सकता है। इसलिए, यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है और देश को विदेशियों, विशेष रूप से चीन द्वारा शोषण से बचा रहा है। एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, स्टार्ट–अप के लिए विभिन्न योजनाएं, भारत को दुनिया का 'खिलौना हब' बनाने के लिए खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन, बजट की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं।

एमएसएमई को प्रोत्साहित करना

बजट सभी स्तरों पर एमएसएमई, स्टार्ट–अप और निर्यात उन्मुख इकाइयों को बढ़ा हुआ ऋण गारंटी कवर देकर एमएसएमई क्षेत्र को नया बढ़ावा देता है; श्रम गहन क्षेत्रों, विशेष रूप से चमड़ा और जूते क्षेत्र, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य के लिए उपाय। विशेष रूप से विनिर्माण मिशन, छोटे, मध्यम, बड़े; सभी प्रकार के उद्योगों को शामिल करते हुए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।

कृषि को बढ़ावा

बिहार के एक अद्भुत पौष्टिक कृषि उत्पाद मखाना को बढ़ावा देने की दिशा में 'मखाना बोर्ड' का गठन अनुकरणीय कदम है और इससे अन्य क्षेत्रों के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। हाल ही में, सरकार ने हल्दी बोर्ड का गठन भी किया है, जिसकी मांग स्वदेशी जागरण मंच यूपीए के दिनों से ही कर रहा था, ताकि तेलंगाना के हल्दी किसानों की चिंताओं को दूर किया जा सके। दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम, कपास मिशन और कृषि के लिए कई अन्य योजनाएं सराहनीय हैं। कई अन्य उपायों के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना भी संतोषजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों से आबादी को स्थानांतरित करने की अनिवार्यता के बयानबाजी के विपरीत, शायद निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में यह कहना अच्छा लगा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन एक विकल्प ही हो, लेकिन अनिवार्यता नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के बढ़ते अवसरों के साथ, सरकार के प्रयासों की बदौलत यह एक संभावना हो सकती है।

ग्रामीण और शहरी भारत के बीच अंतर को पाटना

देश के सामने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आय की असमानता एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह रिपोर्ट आने पर संतोष हुआ कि ग्रामीण और शहरी आबादी में एमपीसीई (मासिक प्रति व्यक्ति व्यय) के बीच का अंतर 84 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत हो गया है। यह ग्रामीण सड़कों, आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण संभव हुआ है। इस प्रक्रिया को और तेज करने की आवश्यकता है।

बजट 2025–26 ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के अलावा, कृषि को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और ग्रामीण आय बढ़ाने के कई अन्य प्रयास ग्रामीण–शहरी असमानताओं को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य को बढ़ावा

केंद्रीय बजट 2025–26 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष और स्वास्थ्य अनुसंधान पर 103280 करोड़ रुपये का व्यय आवंटित किया गया है।

अगर हम पिछले 11 वर्षों को देखें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष और स्वास्थ्य अनुसंधान पर व्यय में 8. 3 गुना वृद्धि हुई है। 2014–15 में यह मात्र ३ करोड़ रुपये से बढ़कर बजट 2025–26 में 103280 करोड़ रुपये हो गया है। इस अवधि के दौरान केंद्रीय बजट का आकार मुश्किल से 2.8 गुना बढ़ा है।

स्वास्थ्य उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाने और अगले पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त सीटों के लक्ष्य के साथ, केंद्रीय बजट 2025–26 में स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का संकेत देते हैं, साथ ही जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट और डे–केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना जैसे प्रमुख उपाय कुछ आवश्यक कदम हैं, जो इस बजट में उठाए गए हैं।

गिग वर्कर

इस बजट में ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले गिग वर्कर्स को मान्यता देने, उन्हें ई–श्रम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने और उन्हें स्वास्थ्य कवर का लाभ देने के अलावा श्रम गहन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का काम किया गया है। लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग कर रहे थे। ❑❑

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला बजट

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट 2025–26 में किए गए प्रस्तावों के मद्देनजर कहा जा सकता है कि इस बजट में मध्य वर्ग को अच्छी खासी तवज्जो दी गई है।12 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर कर से छूट तथा बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा पर विपक्षी दलों की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है तथा वे इसे आगामी विधानसभा के चुनाव से जोड़कर देख रहे है। लेकिन यहां ठहर कर हमें सोचना होगा कि 'बजट 2025–26' बजट भर नहीं है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट अर्थव्यवस्था के नये आयाम को स्वरूप देगा। यह देश की आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और समृद्धि की दिशा में साहसिक कदम है। बजट दूरदर्शी होते हुए भी यथार्थपरक है, और भारत के भविष्य, समावेशी विकास, अपार अवसरों और वैश्विक स्तर पर देश के निरंतर उत्थान से परिभाषित होगा। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति सहित हर वर्ग और हर सेक्टर को सशक्त और सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

जल्द ही भारत दुनिया की सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से होगा और व्यापार, आत्मनिर्भरता तथा वैश्विक प्रभाव में अग्रणी बनेगा। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में बजट सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे।

–अनिल तिवारी

बजट में जहां शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, वहीं मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसका किसान और खेती, दोनों पर व्यापक असर दिखाई देगा। किसान प्रधानमंत्री की उच्च प्राथमिकता हैं। बजट में यह दिखाई भी देता है। देश की 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। खेती की सेहत सुधरेगी तो अर्थव्यवस्था स्वतः ही सशक्त होगी। यही वजह है कि बजट में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। पीएम धन धान्य योजना से देश के 100 जिले और 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का कर्ज देने का प्रावधान किया गया है। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दी गई है। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा।

केंद्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च करेगी तथा रेशेदार कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन लॉन्च किया जाएगा। किसानों को आवश्यकता के अनुरूप यूरिया उपलब्ध कराने के लिए असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। बजट हर वर्ग और हर सेक्टर को

सशक्त और सक्षम बनाने के साथ ही मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करने में मील का पत्थर साबित होगा।

बजट का फोकस विकास में तेजी लाने, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू खर्च में वृद्धि और मध्यम वर्ग को राहत देने तथा उसके सशक्तिकरण पर है। बजट में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आवश्यकता होने पर 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ा कर 1 लाख रुपये कर दी गई है। मध्यम वर्ग राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाली शक्ति बन चुका है। कुल सरकारी राजस्व में आयकर की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से बढ़ कर 22 प्रतिशत हो गई है, फिर भी राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

बजट में देश में सबसे अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये करने का प्रावधान है। स्टार्टअप के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये की जाएगी। गारंटी फीस भी कम की जाएगी। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी। सरकार देश के आईआईटी में अधोसंरचना का विकास करेगी तथा इनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को देखते हुए सरकार एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।

स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। युवाओं में कौशल विकास के लिए पांच नये राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा, रिसर्च और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आईआईटी संस्थानों की क्षमता का विस्तार और क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी जिससे विद्यार्थियों को प्रारंभिक वैज्ञानिक शिक्षा मिलेगी। भारत की तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 30 हजार करोड़ रु पये का आवंटन इन प्रयासों को गति देगा।

बजट में शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं, शहरी कामगारों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लाई जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना से 68 लाख गरीबों को फायदा मिला है। अब गिग और प्लेटफार्म कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई–श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी जिससे एक करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। इन श्रमिकों को आरोग्य योजना के तहते लाभ मिल सकेगा। शहरी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की ऋण की लिमिट बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना शुरू की गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास की प्रतिबद्धता बजट में दिखाई देती है। राज्यों को संरचनात्मक सुधारों के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज–मुक्त 13 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत ऋण दिया गया है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025–30 के तहत 10 लाख करोड़ के नये निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे मौजूदा परिसंपत्तियों से अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा और नये बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा।

जल जीवन मिशन को 2025 तक बढ़ा कर हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। भारत को निवेश–अनुकूल बनाने के लिए प्रगतिशील नियामक सुधार लागू किए जा रहे हैं, जिससे ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार होगा और घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित होंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत ट्रेडनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। जीवनरक्षक दवाओं, टीवी, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और मोबाइल फोन बैटरियों के लिए आयात शुल्क में छूट दी गई है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों, छोटे–मध्यम उद्योगों, बुनियादी ढांचे और आसान नियम–कानूनों पर खास ध्यान दिया गया है, ताकि दीर्घकालिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार हो सके और देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। भारत को कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था परंतु आज हम विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जल्द ही भारत दुनिया की सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से होगा और व्यापार, आत्मनिर्भरता तथा वैश्विक प्रभाव में अग्रणी बनेगा। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में बजट सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे। आम जन को भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीयत साफ और इरादे नेक हैं। उनके लिए स्व हित की जगह राष्ट्र हित सर्वोच्च हैं। राष्ट्र प्रथम और दलीय हित गौण हैं। ❑❑

केंद्रीय अर्थ संकल्प 2025–26

निशाने पर तीर

भारतीय राजधानी नई दिल्ली विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि केंद्रीय अर्थ संकल्प 2025–26 ठीक समय पर पेश किया गया और इसमें किए आर्थिक प्रस्तावों ने जनता का दिल जीत लिया। परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया। वैसे पिछले कुछ वर्षों से अर्थ संकल्प को लेकर आम जनता में एक प्रकार की उदासीनता देखी जा रही थी। इसके विपरीत, इस वर्ष के अर्थ संकल्प में व्यक्तिगत आयकर दरों में किए गए बदलाव और 12 लाख रुपये तक की आय पर कर–मुक्ति के कारण मध्यम वर्ग में उत्साह दिखाई दिया। अर्थ संकल्प के प्रति जनता की उदासीनता का मुख्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रही सामान्य स्थिरता कहा जा सकता है। ऐसी स्थिरता के दौर में अर्थव्यवस्था प्रगतिशील रहती है और समय के साथ उत्पन्न होने वाली समस्याओं के अनुसार अपेक्षित बदलावों को सहज रूप से समाहित कर लेती है। इसलिए किसी बड़े, मूलभूत या कठोर निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में सरकार भी अपने नीतिगत फोकस को आर्थिक मुद्दों से समाज कल्याण की दिशा में मोड़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रही इस स्थिरता का श्रेय निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को दिया जाना चाहिए। यह पिछले दस वर्षों में लागू की गई नीतियों का परिणाम है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाली घटनाएँ नहीं होतीं। ऐसी घटनाएँ घटित होती रहती हैं, कभी जानबूझकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पन्न की जाती हैं। साथ ही, इस स्थिरता का अर्थ यह भी नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कोई चुनौतियाँ नहीं हैं। बेरोजगारी और कृषि उत्पादन व उत्पादकता की समस्या आज भी विद्यमान है। महंगाई भी समय–समय पर चिंता का विषय बनती रहती है। कृषि विकास का वास्तविक लाभ सामान्य किसान तक नहीं पहुँच पाता, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता ही है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। ऐसे समय में यह नया अर्थ संकल्प यह संकेत देता है कि सरकार किस प्रकार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है और साथ ही आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है।

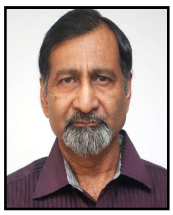

बजट में विकसित भारत का लक्ष्य संजोते हुये इस विकास यात्रा के लिए चार शक्तिशाली इंजन की बात की गई है जो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात है और उसका ईंधन हैं आर्थिक सुधार।

– अनिल जवलेकर

अर्थ संकल्प नई दिशा

'आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25' भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत और स्थिर विकास पथ को उजागर करता है। इसके मुताबिक बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय स्थिरता, और दीर्घकालिक सुधारभारत के विकास को गति देंगे। हालाँकि मुद्रास्फीति, वैश्विक अस्थिरता, और कृषि उत्पादकता जैसे मुद्दे चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर लचीली

और प्रतिस्पर्धी बनी हुई है, जो आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरने की क्षमता रखती है। इसलिए अर्थ संकल्प नई दिशा को स्पष्ट करते हुए विकास की बात करता है। यह अर्थ संकल्प विकास में तेजी लाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालने, सामान्य परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरने, और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों में स्पष्टता लाता है।

क्या है विकास में तेजी का अर्थ

अर्थ मंत्री ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि विकास का अर्थ गरीबी से मुक्ति, शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शत–प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं, और हमारे देश को 'फूडबास्केट ऑफ द वर्ल्ड' बनाने वाले किसान। इस अर्थ संकल्प में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर दस व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जिसमें कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और 'मेक इन इंडिया' को और आगे ले जाना, छोटे एवं माध्यम उद्योगों को सहायता देना, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, और नवाचार को पोषित करना। बजट में विकसित भारत का लक्ष्य संजोते हुये इस विकास यात्रा के लिए चार शक्तिशाली इंजन की बात की गई है जो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात है और उसका ईंधन हैं आर्थिक सुधार।

क्या कुछ है अर्थ संकल्प में ?

1. सबसे पहले किसान और कृषि की बात। पहले से चल रहे उपक्रम जैसे, राष्ट्रीय विकास योजना, बीमा फसल योजना, किसान सम्मान, किसान मानधन, समर्थन मूल्याधारित खरीद तथा कृषि विकास में सहायक ऐसी सारी योजनाएँ जिनका कृषि विकास और किसान को सीधे मदद मिलने में अच्छा योगदान रहा है, वे जारी रहेंगी। नए उपक्रम में बदलते पर्यावरण में उपयोगी बीजों का संशोधन और उत्पादन, मखाना बोर्ड, फल–सब्जी तथा दाल के उत्पादन में बढ़त के लिए योजना, कृषि उत्पादन में विविधता लाना, ब्याज राहत की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख करना वगैरे शामिल है, जिसका कृषि और किसान को लाभ ही मिलेगा।

2. सीधा लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा। 12 लाख रुपए तक आयकर से मुक्त करना सबसे बड़ी राहत कही जा सकती है। कर–दर में बदलाव भी बहुत से आयकर दाताओं को लाभ पहुंचाएगा। अर्थमंत्री का यह आश्वासन कि कर व्यवस्था सरल की जाएगी और कानूनी दावे खासे कम होंगे, यह अपने आपमें बड़ा कदम है।

3. भारतीय सामान्यों के लिए डाकघर आज भी संपर्क और निवेश का साधन बना हुआ है। लेकिन निजीकरण के दौर में यह व्यवस्था पीछे छूट गई थी। इसलिए इसका उल्लेख कर अर्थ संकल्प में प्रोत्साहन देना अच्छी बात कही जाएगी। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा तथा भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा। इससे विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्व–सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

4. अर्थ संकल्प में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए भी उपयुक्त बहुत कुछ है, जैसे कि गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करना, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड देना, स्टार्ट–अप के लिए निधियों का कोष बनाना, पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना, श्रम–सघन क्षेत्रों के लिए उपाय, फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, विनिर्माण मिशन – 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण इत्यादि।

अर्थ संकल्प में जिस बात का उल्लेख होना जरूरी है, वह है – लोगों में निवेश। इसको ध्यान रखते हुए अर्थमंत्री ने कुछ घोषणाएँ की है जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी, सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी, भारतीय भाषाओं में डिजीटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाभकारी होगी।

केंद्रीय 'अर्थ संकल्प 2025–26' समावेशी और दूरदर्शी है, जो न केवल आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। यह अर्थ संकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्थिर और प्रगतिशील दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन करेगा, जिससे भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रख सकेगा। ❑❑

वित्तीय वर्ष 2025–26 का अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट

दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया। श्रीमती सीतारमन ने एक महिला वित्तमंत्री के रूप में लगातार 8वां बजट लोकसभा में पेश कर एक रिकार्ड बनाया है। वित्तमंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया बजट अपने आप में पथप्रदर्शक, अग्रणी एवं अतुलनीय बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इस बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पिछले कुछ समय से देश की अर्थव्यस्था में विकास की गति कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी अतः विशेष रूप से मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के हाथों में अधिक धनराशि शेष बच सके ताकि वे विभिन्न उत्पादों को खरीदकर अर्थव्यवस्था में इनकी मांग बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। साथ ही, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से रोजगार उन्मुख क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश, निर्यात एवं समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इन्हें विकास के इंजिन के रूप में विकसित किया जा सके।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से रोजगार उन्मुख क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश, निर्यात एवं समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इन्हें विकास के इंजिन के रूप में विकसित किया जा सके।

–प्रहलाद सबनानी

भारत में मध्यमवर्गीय परिवार देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आया हैं। हाल ही के समय में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में व्यक्तिगत आयकर की भागीदारी कारपोरेट क्षेत्र से आयकर की भागीदारी से भी अधिक हो गई है। अतः मोदी सरकार से अब यह अपेक्षा की जा रही थी कि मध्यमवर्गीय परिवारों को बजट के माध्यम से कुछ राहत दी जाय। और फिर, मुद्रा स्फीति की सबसे अधिक मार भी गरीब वर्ग के परिवारों एवं मध्यमवर्गीय परिवारों पर ही पड़ती दिखाई देती है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर की वर्तमान सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अर्थात अब 12 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगेगा। वेतन एवं पेंशन पाने वाले नागरिकों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती की राहत इसके अतिरिक्त प्राप्त होगी। इस वर्ग के करदाताओं को 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं चुकाना होगा। इसके साथ ही, आय कर की दरों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 4 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर शून्य रहेगी। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर 5 प्रतिशत, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर 25 प्रतिशत एवं 24 लाख रुपए से अधिक की कर योग्य आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा। मध्यमवर्गीय करदाताओं को उक्त सुधारों से लगभग 80,000 रुपए से 1.10 लाख रुपए तक की राशि की बचत होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस सुधार से कुल मिलाकर देश के बजट

में एक लाख करोड़ रुपए की राशि कम प्राप्त होगी अर्थात मध्यमवर्गीय परिवारों को कुल एक लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का लाभ होगा। यह लाभ लगभग 2 करोड़ करदाताओं को होने की सम्भावना है। इससे देश के मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों के हाथों अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी जिसे वे विभिन्न उत्पादों की खरीद पर खर्च करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होंगे। मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों ने जितना सोचा था शायद उससे भी कहीं अधिक राहत उन्हें इस बजट के मध्यम से दी गई है। इसीलिए ही, इस बजट को अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट की संज्ञा दी जा रही है।

मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों को, आयकर में छूट देकर, दी गई राहत देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे बजटीय घाटा में वृद्धि नहीं हो। वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने की सम्भावना पूर्व में की गई थी, परंतु अब संशोधित अनुमान के अनुसार यह बजटीय घाटा कम होकर 5.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजटीय घाटा 5.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। अतः देश की वित्तीय व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हां, पूंजीगत खर्चों में जरूर कुछ कमी रही है और वित्तीय वर्ष 2024–25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च के अनुमान के विरुद्ध 10.18 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में 11.12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था बजट में की गई है। इस राशि को 11.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए किया जाना

श्री अयोध्या धाम, महाकुम्भ क्षेत्र प्रयागराज, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, महाकाल मंदिर उज्जैन की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा ताकि देश में धार्मिक पर्यटन की गतिविधियों को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके।

चाहिए था क्योंकि पूंजीगत खर्च में वृद्धि से देश में आर्थिक विकास की दर तेज होती है और रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। इस संदर्भ में एक रास्ता यह निकाला गया है कि केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों से अपेक्षा की गई है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में ये संस्थान भी अपने पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करें ताकि उनके द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों की राशि को मिलाकर कुल पूंजीगत खर्च को 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाया जाए।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि धन धान्य योजना को 100 जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है, इस योजना के माध्यम से इन जिलों में ली जा रही फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दलहन के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 5 लाख तक बढ़ाया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए एवं स्टार्टअप के लिए ऋण की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जा रहा है। लेदर उद्योग में रोजगार के 22 लाख नए अवसर निर्मित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को खिलौना उत्पादन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाया जाएगा। आज भारत खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात करता है अतः तिलहन के क्षेत्र में भी आत्म निर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।। भारत में निर्मित विभिन्न उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों की तलाश करते हुए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सम्पन्न किए जा रहे हैं। देश में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जा रही है। विभिन्न शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाया जा रहा है।

युवाओं में कौशल विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, आगामी 5 वर्षों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 युवाओं को अतिरिक्त दाखिला दिए जाएंगे। इंडियन इन्स्टिटूट आफ टेक्नॉलजी कॉलेजों में टेक्नलाजिकल रीसर्च के लिए 10,000 पी एम स्कालर्शिप प्रदान की जाएंगी एवं नए आईआईटी केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। आरटीफिशियल इंटेलीजेंस सेंटर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

श्री अयोध्या धाम, महाकुम्भ क्षेत्र प्रयागराज, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, महाकाल मंदिर उज्जैन की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा ताकि देश में धार्मिक पर्यटन की गतिविधियों को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके। देश में 52 नए पर्यटन केंद्र भी विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है तथा भगवान बुद्ध सर्किट भी विकसित किया जाएगा। ❑❑

(सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.)

एमएसएमई को बढ़ावा एवं युवाओं को रोजगार देने वाला बजट

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आठवीं बार बजट प्रस्तुत किया। बजट में गरीब, युवा, महिला और किसान पर विशेष बजट दिया गया। बजट 2025–26 में एमएसएमई को 5000 करोड़ से 10000 करोड़ रूपये। स्टार्टअप के लिए 10 से 20 करोड़ से युवाओं को उद्योग लगाने एवं रोजगार में वृद्धि होगी। 10000 मेडिकल सीट बढ़ाई गई। शोध के लिए 12000 करोड़ से 20000 करोड किये गये है। आईआईटी में 65000 सीट बढ़ाई गई है। अटल टिंकरिंग लैब्स 50000 स्कूलों को देने की बात की गई है, जिससे शोध एवं विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख लोगों को रोजगार के साथ–साथ खिलौना के लिए ग्लोबल हब बनाने की बात बजट में की गई है।

किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में कृषि के लिए सस्ते कर्ज, सिंचाई के लिए भी पुख्ता व्यवस्था, उत्पादन का उचित मूल्य की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने एवं जिला स्तर पर कृषि निर्यात केन्द्र को मजबूती प्रदान करने की बात की है।

गांव और ग्रामीणों को समर्पित यह बजट

गांवों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर किसानों की समस्याओं सहित सभी की चिंता इस बजट में की गई हैं। हरित क्रांति को गतिशील करने के साथ ही किसानों को सुविधा संपन्न बनाने की रणनीति बनायी गई है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटन को बढ़ा हैं।

कृषि आधारित उद्योग, रोजगार को प्राथमिकता एवं जल संरक्षण के विशेष प्रयास इस बजट में किए गये है।
– डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा

कृषि आधारित उद्योग, रोजगार को प्राथमिकता एवं जल संरक्षण के विशेष प्रयास इस बजट में किए गये है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट गांवों में सड़कें, बिजली, पानी, आवास, स्वच्छता के साथ ही विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा को बढ़ावा देने वाला है। खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास उत्पादकता मजबूत करने वाला यह बजट निश्चित रूप से ग्रामीण विकास और कृषि विकास को मजबूती प्रदान करेगा। बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई, जिसमें देश के उन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां कम पैदावार, आधुनिक कृषि उपकरणों की कमी और औसत से कम ऋण सुविधा जैसी चुनौतियां हैं। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। ग्रामीण विकास

को 266817 करोड़ रूपये दिए गए हैं। कृषि को 171437 करोड़ रूपये दिए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र को 128650 करोड़ रूपये दिए गए हैं। सामाजिक विकास एवं कार्य के लिए 60052 करोड़ रूपये दिए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र को 81174 करोड़ रूपये दिए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 11 प्रतिशत बढ़ाकर 98,311 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश योजनाओं में बजट आवंटन बढ़ाया गया है। जैसे आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना का बजट अनुमान 9,406 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि 2024–25 का संशोधित अनुमान 7,606 करोड़ रुपए था। यानी इस योजना में करीब 24 प्रतिशत अधिक राशि का आवंटन का प्रावधान हुआ है। सिंचाई एवं उर्वरक को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

रोजगार एवं कृषि विकास के लिए कर्ज और लोन की सीमा बढ़ाई सरकार ने इस बजट में। बजट में पुरानी योजनाओं का बजट बढ़ाने पर जोर। शासकीय क्षेत्र में रोजगार एवं कोई विशेष परिवर्तन बजट में नहीं। 15.69 लाख करोड़ घाटे का बजट, लेकिन 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश इस बजट में की गई है।

निश्चित रूप से इस बजट में युवाओं के लिए नौकरी, शिक्षा, शोध पर विशेष बल दिया गया है। रेलवे, बैंक, शिक्षा क्षेत्र में अभी भी 65 प्रतिशत से अधिक रोजगार की संभावनाएं है।

केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2025–26 में महाकौशल के युवाओं एवं किसानों को रोजगार एवं कृषि कार्य में एमएसएमई एवं स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार, कृषि आधारित उद्योग मजबूत होंगे, महाकौशल के अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए उद्योग लगाने हेतु सरकार के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसानों को अब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख से 5 लाख रूपये दिए जाएंगे। 10000 मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाई गई है। इसका लाभ महाकौशल के युवाओं को भी होगा। स्टार्टअप को 10 करोड़ का फंड एवं एमएसएमई को 20 करोड़ रूपये के फंड से युवा एवं उद्योग में तेजी आयेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए महाकौशल को 150 लाख करोड़ रूपये मिलने वाले हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। रिसर्च में 12000 करोड़ से 20000 करोड़ दिए गए हैं, पीएम रिसर्च फेलो का लाभ युवा भी ले सकते हैं।

महाकौशल क्षेत्र में उद्योग एवं रोजगार के आने से मंडला, डिंडौरी जिले के महिलाएं अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिससे महाकौशल क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी आयेगी।

ग्रामीण विकास को 266817 करोड़ रूपये दिए गए हैं। कृषि को 171437 करोड़ रूपये दिए गए हैं। सामाजिक विकास एवं कार्य के लिए 60052 करोड़ रूपये दिए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र को 81174 करोड़ रूपये दिए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 11 प्रतिशत बढ़ाकर 98,311 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सिंचाई एवं उर्वरक को विशेष प्राथमिकता दी गई है। रोजगार एवं कृषि विकास के लिए कर्ज और लोन की सीमा बढ़ाई सरकार ने इस बजट में।

केंद्रीय बजट में जबलपुर में उद्योगों, जिसमें प्रमुख रूप से जीसीएफ फैक्टरी, बीएसएनएल, रेलवे लाईन एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी रोजगार की संभावना है। इसके साथ–साथ जबलपुर को नई रेल लाईन, जिसमें मंडला और डिंडोरी जिले को जोड़ने तथा जनजाति क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग की भी संभावना है। जबलपुर के पाटन, नरसिंहपुर जो कृषि क्षेत्र है इन क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग की संभावना अधिक है।

❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दुनिया भर में बढ़ रहा है रक्षा का बजट

केंद्रीय बजट 2024–25 में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए जो सभी मंत्रालयों से ज्यादा है और यह वित्त वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत ज्यादा है।पूंजी के अधिग्रहण के लिए 1.72 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए, जीविका और परिचालक तत्परता के लिए 92 हजार 88 करोड रुपए दिए गए, रक्षा पेंशन बजट के लिए 1.41 लाख करोड रुपए का आवंटन किया गया है, वहीं सीमा पर सड़कों के विकास के लिए 6500 करोड रुपए तथा तटीय सुरक्षा के लिए 7651 करोड रुपए आवंटित हुए हैं। सरकार ने दावा किया है कि वह पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य और उसकी सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए विशेष बजट का प्रावधान है।

मालूम हो कि पाकिस्तान सरकार का वर्ष 2024–25 के लिए रक्षा खर्च 59.42 हजारकरोड रुपए है जो कि भारत के मुकाबले बहुत कम है, जबकि दूसरे पड़ोसी चीन ने रक्षा बजट 236 अरब डॉलर कर रखा है। चीन के मुक़ाबले भारत का रक्षा बजट बहुत कम है। अगर चीन के रक्षा बजट में अन्य कॉरपोरेट फंडिंग को जोड़ दिया जाए तो यह 711 अरब डॉलर के बराबर है जो कि अमेरिका के सैनिक खर्च 875 बिलियन डॉलर के स्तर के करीब है। यानी पड़ोसी चीन रक्षा बजट पर कमोबेस अमेरिका से टक्कर ले रहा है। भारत अभी भी बहुत पीछे है।

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें रक्षा बजट की भी घोषणा की। इस बार रक्षा बजट में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक–ठाक वृद्धि की गई है। कई लोगों का मानना है कि भारत को रक्षा पर और ज्यादा खर्च करना चाहिए। बजट में सरकार का फोकस इस बात पर रहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। अगर भारत का जीडीपी बढ़ेगा, तभी रक्षा खर्च भी बढ़ पाएगा। इसलिए सरकार का ध्यान अभी ग्रोथ तेज करने पर है।

रक्षा क्षेत्र में भारत पिछले कई सालों से बहुत सारे सुधार कर रहा है। चाहे वह हथियारों की खरीद हो, कोई बदलाव या फिर मानव संसाधन की बात हो। अभी देश के रक्षा बजट का ज्यादातर हिस्सा पेंशन और सैलरी में जा रहा है। हाल यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। यहां पर एक बात यह है कि भारत को कैपिटल एक्सपेंडिचर (असेट्स तैयार करना) की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बड़े–बड़े हथियार और प्लैटफॉर्म खरीदने हैं, वे तभी मिल पाएंगे जब रक्षा बजट का और प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाए। इसे देखते हुए ही भारत ने इस पर फोकस करने की कोशिश की है कि आर्थिक नीतियां बदलें और सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था गति पकड़े।

दुनिया में अगर रक्षा बजट बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि यही सारे मुद्दे मिलकर इस पर असर डाल रहे हैं। इसके चलते रक्षा बजट दुनिया भर में बढ़ रहा है और आगे भी यही लग रहा है कि यह बढ़ता रहेगा।

– गणेश गौतम

बाकी दुनिया में भी इस समय लगभग सभी देशों का रक्षा बजट बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि दुनिया में असुरक्षा का माहौल है। कई युद्ध चल रहे हैं। रूस–यूक्रेन का युद्ध हो या गाजा में इस्राइल का युद्ध, दोनों ही बड़ी परेशानियां हैं। मिडल ईस्ट में हालांकि सीजफायर हो चुका है, फिर भी वहां पर माहौल काफी तनावग्रस्त बना हुआ है। रूस–यूक्रेन युद्ध की जहां तक बात है तो उसे रोकने पर बात अभी बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ी है। यही नहीं, अमेरिका और चीन के बीच जो परेशानियां हैं, जो प्रतिद्वंद्विता है, वह तेज हो रही है।

इसलिए बड़ी ताकतें रक्षा बजट बढ़ा रही हैं। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बड़े–बड़े प्रॉजेक्ट्स का ऐलान किया है। उनमें से एक आयरन डोम है। ट्रंप एक मिसाइल डिफेंस शील्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं। चीन भी इसे देखते हुए पिछले कुछ सालों से लगातार डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। चीन के साथ समस्या और भी है कि उसमें ट्रांसपेरेसी नहीं है। चीन जितने की घोषणा करता है, उससे कई गुना ज्यादा खर्च करता है। इसके चलते चीन के खिलाफ दुनिया भर में एक संदेह भी है।

रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों पर यह दबाव है कि वे भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। नैटो के सदस्य देश भी अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। रूस के पड़ोसी देश भी थोड़े से डरे हुए हैं। जबसे यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया है, उसके बाद से उन देशों का भी रक्षा बजट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चीन ने हिंद–प्रशांत के इलाके में जिस तरह का माहौल बनाया है, उसके चलते जापान अपनी डिफेंस पॉलिसी बड़ी तेजी से बदल रहा है। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कई साउथ–ईस्ट एशिया के देश भी रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं।

इस समय जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की अव्यवस्था बनी हुई है, हमारे मल्टिलैटरल इंस्टिट्यूशंस भी काम नहीं कर रहे हैं– इनको देखते हुए दुनिया भर के देशों का रक्षा बजट बढ़ रहा है। रक्षा बजट बढ़ाने का एक प्रभाव यह भी हो रहा है कि विभिन्न देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि इन तमाम देशों के पास ऐसा कोई तरीका उपलब्ध नहीं है कि वे सब साथ मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दों पर अपना ध्यान लगा सकें। इसके चलते ग्लोबल गवर्नेंस को दरकिनार करके इस समय हर देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है।

आर्थिक तौर पर भी अगर देखें तो संरक्षणवाद बढ़ रहा है। यह आर्थिक असुरक्षा का रूप ले रहा है, क्योंकि लोग परेशान है, असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। दुनिया में अगर रक्षा बजट बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि यही सारे मुद्दे मिलकर इस पर असर डाल रहे हैं। इसके चलते रक्षा बजट दुनिया भर में बढ़ रहा है और आगे भी यही लग रहा है कि यह बढ़ता रहेगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

डिजिटल होती दुनिया में भी बरकरार है रेडियो का जादू

हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में याद किया जाता है, यह तिथि यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को विश्व रेडियो दिवस के लिए निर्धारित की गई। यह निर्णय यूनेस्को की 36वीं कांफ्रेंस के दौरान लिया गया था। इसके लिए स्पेनिश रेडियो ने यूनेस्को से आग्रह किया था। विश्व रेडियो दिवस का पहला आयोजन 2012 में किया गया, जिसमें दुनिया भर के रेडियो प्रोफेशनल शिक्षाविद् और विषय से संबंधित रूचि रखने वाले व्यक्ति शामिल हुए। सही अर्थों में रेडियो ने सूचना देने, शिक्षा देने और मनोरंजन प्रदान करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है।

डिजिटलीकरण के इस दौर में इंटरनेट की चाल देख ऐसा प्रतीत होने लगा था कि रेडियो की आवाज दबकर रह जायेगी। लेकिन रेडियो अपनी अंतर्निहित विशिष्टताओं के कारण निरंतर जन–जन तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने के क्रम में एक प्रासंगिक माध्यम के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है।

शहरों में लोग आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन कस्बों व गांवों में अभी भी रेडियो सुना जाता है। जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं, वहां भी रेडियो उपस्थित है, सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक।

जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, वे अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन रेडियो सुन सकते हैं। जो लोग अपनी दृष्टिहीनता के कारण न तो अखबार पढ़ सकते हैं, न टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो उनका भी साथी है और पथप्रदर्शक भी। तीसरी दुनिया के देशों में रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिसे वास्तव में जन माध्यम कहा जा सकता है।

रेडियो श्रोताओं को साथ लेकर चलता है और वह उनकी बुद्धि, सोच, और कल्पनाशक्ति पर भरोसा करता है और उन्हें विस्तार तथा सोचने की खुराक भी देता है। चाहे किचन में काम करती हुई महिलाएं, रातों में पहरा देते चौकीदार, सीमा पर देश की रखवाली करते हुए जवान या दफ्तर से घर आने–जाने के दौरान ट्रैफिक में फँसे लोगों का रेडियो एक हमजोली

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रेडियो ऐसा माध्यम है जो जनमाध्यम का वृहद रूप ग्रहण किए हुए है और यह अपनी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है।

– शिवनंदन लाल

की तरह साथ तो निभाता ही है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नित नए अनुसंधानों से भी लोगों को परिचित कराता है।

भारत देश में रेडियो की विधिवत शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। आजादी के बाद से आकाशवाणी विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत नेटवर्क वाला संस्थान बन चुका है। आजादी के समय हमारे पास केवल छह रेडियो स्टेशन और 18 ट्रांसमीटर थे, उस समय इसकी पहुंच देश के केवल 2.5 प्रतिशत क्षेत्र तक सीमित थी और देश की केवल 11 प्रतिशत जनसंख्या ही आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन पाती थी। आज हमारे पास आकाशवाणी के 233 केंद्र तथा 375 ट्रांसमीटर हैं। फोन इन सेवा से लेकर पॉडकास्ट तक की सुविधा है। आज आकाशवाणी की पहुंच देश के कोने–कोने में समस्त लोगों तक है।

आकाशवाणी मात्र मनोरंजन का साधन कभी नहीं रहा। जन प्रसारकर्त्ता के रूप में यह न केवल अनिवार्य रूप से लोगों को शिक्षित करता है बल्कि स्वस्थ मनोरंजन के साथ–साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक स्वास्थ्य,सामाजिक और आर्थिक पहलू तथा राष्ट्रीय एकीकरण पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित कर श्रोताओं तक सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों के विषय में जानकारी पहुंचाकर एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका को बल प्रदान करता है।

इस प्रकार वर्तमान समय में रेडियो की प्रासंगिकता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भी समझा जा सकता है।

भारत के संदर्भ में बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक एवं बहुस्तरीय जनता की अपनी विशिष्ट आवश्यकता है। यहां स्थानीय रेडियो केंद्रों में अपार वृद्धि होनें से स्थानीय लोग अपनी भाषा, रुचि, आवश्यकताओं एवं समय के अनुरूप कार्यक्रम में भागीदार होते हैं। रेडियो अपनी इसी विशिष्टता के कारण जन–साधारण तक पहुंचने में सफल रहा है। और यह तत्व भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को सुदृढ़ता प्रदान करता है।

भारत के संदर्भ में बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक एवं बहुस्तरीय जनता की अपनी विशिष्ट आवश्यकता है। यहां स्थानीय रेडियो केंद्रों में अपार वृद्धि होनें से स्थानीय लोग अपनी भाषा, रुचि, आवश्यकताओं एवं समय के अनुरूप कार्यक्रम में भागीदार होते हैं। रेडियो अपनी इसी विशिष्टता के कारण जन–साधारण तक पहुंचने में सफल रहा है। और यह तत्व भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को सुदृढ़ता प्रदान करता है।

रेडियो के संदर्भ में किसी ने सच ही कहा है कि – 'रेडियो कोई तकनीकी संदूक नहीं अपितु जीवंत व प्रगतिशील सूचना, अद्यतन ज्ञान विज्ञान एवं मनोरंजन के खजाने का भंडार है।'

इंटरनेट के बढ़ते प्रसार तथा वक्त बदलने के साथ–साथ लोगों के संचार व मनोरंजन के साधन में भी बदलाव हुआ है, मगर आज तक जो चीज नही बदली वह रेडियो के प्रसारण और एक ट्रांजिस्टर के माध्यम से आती आवाज के जरिए घंटों चिपके रहनें की वह बेकरारी।

आज भी देश के अधिकांश घरों से पारंपरिक रेडियो के बजने की आवाज सुनाई देती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रेडियो ऐसा माध्यम है जो जनमाध्यम का वृहद रूप ग्रहण किए हुए है और यह अपनी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति भी इसके द्वारा उच्चरित शब्दों को सुनकर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुभूति करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी अनिवार्य है। कहा भी गया है कि – "आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है" और उसके इस जादू का उपयोग सामाजिक व राष्ट्रीय उत्थान के लिए किया जाना उचित ही है जो रेडियो की प्रासंगिकता को भविष्य में भी बनाए रखेगा। ❑❑

(वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी नई दिल्ली)

पर्यटन के विस्तार से अर्थव्यवस्था को मजबूती

ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री भारत की ऐसी इंडस्ट्री है, जो बिना कोई शोरशराबा मचाए चुपचाप भारत की ग्रोथ को बढ़ा रही है। पर्यटन क्षेत्र भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में करीब 5 प्रतिशत का योगदान देता है। केंद्रीय बजट 2025–26 में सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और यातायात संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 2541.06 करोड रुपये आवंटित किए हैं। पिछले वित्त वर्ष में ट्रैवल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में 850.36 करोड़ रुपये खर्च किए जबकि इस साल पिछले साल की अपेक्षा भारी वृद्धि की गई है।

भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 256 बिलियन डॉलर है और यह बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारतीय पर्यटक स्थलों पर 2023 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन यानी आईटीए 1.45 प्रतिशत रहा और पर्यटन के माध्यम से 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की आय हुई थी। भारत को विश्व पर्यटन का 1.8 प्रतिशत हिस्सा मिला और वर्ष 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत का 14वां स्थान था। वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र में 7.6 करोड़ नौकरियां भी सृजित हुईं। पर्यटन क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013 में जीडीपी में करीब 5 प्रतिशत का योगदान था लेकिन कोरोना महामारी का इस पर प्रभाव पड़ा और अब यह पुनः पिछले आंकड़ों पर पहुंच गया। पर्यटन के सभी क्षेत्रों में होने वाला विकास हालांकि बराबर नहीं है, इस विकास को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा बजट रखा है।

पर्यटन क्षेत्र में भारत में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि सभी क्षेत्रों में अभी पूरी तरह से नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यटन स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के मामले में देश के बड़े शहरों में तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र अभी काफी पिछड़ा हुआ है। विशेष रूप से अविकसित और अनदेखे गंतव्यों में पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने की जरूरत है। देश में बहुत से विरासत संपन्न पर्यटन स्थल

सरकार को चाहिए कि वह प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास करें और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक साझी रणनीति तैयार कर आगे बढ़े।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

हैं, लेकिन ये स्थल पूरी तरह से सड़क मार्गों से संपन्न नहीं हैं। यहां पर समुचित सुविधाएं भी नहीं हैं जबकि ये बहुत प्रसिद्ध हैं। इसे सुदृढ़ करने के लिए बजट में योजनाओं को रखा गया है।

कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर

अब सरकार इन पर्यटन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कनेक्टिविटी विकसित करना चाहती है यानी इन स्थानों पर सुगम सड़कें, यातायात के साधन और ठहरने के लिए बेहतरीन होटल, मार्केट और अंतरराष्ट्रीय एमेनिटीज मुहैया करने का मन बनाए हुए है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पर्यटन क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से संपन्न किया जाएगा। इन क्षेत्रों में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण देने का प्रावधान किया गया है। चुनौती के तौर पर सरकार ने प्रमुख पहल करते हुए देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी कर 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। नॉर्थ ईस्ट ओर जम्मू–कश्मीर में बहुत से धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट किया जाएगा।

धार्मिक पर्यटन के तहत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व को पहचानते हुए बजट में तीर्थ यात्रा और विरासत से जुड़े स्थलों का विकास किया जाएगा। इनमें बौद्ध पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरोध पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े स्थानों पर विशेष जोर दिया गया है। उड़ान योजना के विस्तार से 10 वर्ष में 120 नये गंतव्यों पर एयरपोर्ट का निर्माण करने और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देनें को छोटे एयरपोर्ट बनाए जाने से धार्मिक, आध्यात्मिक और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। होटल, रिसोर्टस और होमस्टे की मांग में वृद्धि होगी। चुनिंदा देशों के पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क में छूट और ई–वीजा सुविधा से यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाने से पर्यटन क्षेत्र में विकास की तमाम संभावनाएं जागृत होंगी।

भारत में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है। इसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों की समुचित सफाई की जानी चाहिए। पीने का पानी, भोजन, शौचालय के साथ-साथ चिकित्सा की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्य उद्योगों की तुलना में पर्यटन क्षेत्र में कम विनियोग से ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री बजट अनुकूल और टिकाऊ पर्यटन का समर्थन करती है। होटल इंडस्ट्री की जीएसटी को तर्कसंगत बनाने और टीसीएस को कम करने की भी मांग रही है। बजट और हॉस्टल श्रेणी के आवासों के लिए जीएसटी दरों को कम करने से लोगों की यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी। इससे भारत के मध्यमवर्गीय पर्यटकों को लाभ के साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है। इसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों की समुचित सफाई की जानी चाहिए। पीने का पानी, भोजन, शौचालय के साथ–साथ चिकित्सा की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पर्यटकों के ठहरने के लिए सस्ती दर पर विश्रामस्थल बनाने चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बस, टैक्सी, कैब आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यटन उद्योग से कई लघु उद्योग भी जुड़े हुए हैं। सैलानी घूमने के साथ–साथ उन स्थलों की विशेष वस्तुओं को भी खरीदना चाहते हैं। अतः स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानदारों को बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को देश में विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों से तालमेल बनाकर समस्याओं को हल करना चाहिए। पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी बड़ी समस्या है। पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करनी चाहिए। इसी तरह नवाचार को अपनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। आधारभूत संरचनाओं जैसे परिवहन, रहने की व्यवस्था व पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का प्रचार–प्रसार कर पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जा सकता है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पर्यटन स्थलों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आवागमन के अनुकूल बनाना चाहिए। करों में कमी करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार होना चाहिए। पर्यटन स्थलों को सड़क, रेल और वायु मार्ग से जोडऩा चाहिए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के साधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पर्यटन स्थलों पर सफाई, सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं व पेयजल की सुचारू व्यवस्था आवश्यक है। पर्यटक सहायता केन्द्र पर पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी हों एवं पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी देने वाला साहित्य हो।

पर्यटन स्थलों का अच्छे प्रकार से रखरखाव किया जाए, उन्हें अधिक आकर्षक बनाया जाए। सैलानियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सरकार को चाहिए कि वह प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास करें और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक साझी रणनीति तैयार कर आगे बढ़े। ❑❑

क्या भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा

आज भारत के संदर्भ में यह सपना देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के बल पर वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। परंतु, सकल घरेलू उत्पाद में औसतन लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ क्या भारत वास्तव में वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा अथवा भारत को अभी भी कई प्रकार के सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी देश को अपनी आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए कई प्रकार के सुधार कार्यक्रम लागू करने होते हैं। भारत ने वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, एक लम्बे अंतराल के पश्चात देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को वर्ष 1991 में प्रारम्भ किया। जबकि इस समय तक अमेरिका एवं कई यूरोपीय देश विकसित राष्ट्र बन चुके थे एवं चीन ने तो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को वर्ष 1980 में ही लागू कर दिया था तथा अपनी वार्षिक आर्थिक विकास दर को दहाई के आंकड़े के भी पार ले गया था। भारत इस मामले में बहुत पिछड़ चुका था।

श्री राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1985–86 में भारतीय संसद में एक सुधारवादी बजट पेश जरूर किया था परंतु वे इन कार्यक्रमों को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए। परंतु, वर्ष 1991 में श्री नरसिम्हा राव सरकार ने देश में लाइसेन्स राज को समाप्त कर सुधारवादी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। इसके पूर्व निजी क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में उचित स्थान प्राप्त नहीं था और केवल पब्लिक सेक्टर के दम पर ही भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था। तात्कालीन केंद्र सरकार द्वारा समाजवादी नीतियों को अपनाए जाने के चलते भारत में सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करने में बहुत अधिक देर कर दी गई थी। वर्ष 1947 में भारत के राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात बड़े उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पेट्रोलियम रिफाइनरी,

भारत में केवल भूमि, पूंजी एवं श्रम की लागत को कम करने में यदि सफलता हासिल की जा सके तो भारत की आर्थिक विकास दर को 10 प्रतिशत से भी ऊपर ले जाया जा सकता है। भूमि, पूंजी एवं श्रम जहां भी आसानी से एवं उचित दामों पर उपलब्ध होंगे वहां उद्योग धंधे आसानी से फलेंगे एवं फूलेंगे।

– स्वदेशी संवाद

मशीनरी एवं तकनीकी उद्योगों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया जबकि आज यह समस्त उद्योग देश में अत्यधिक सफल होकर देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं।

वर्तमान में केंद्र सरकार 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हाल ही के वर्षों में लागू किए गए सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं – वस्तु एवं सेवा कर बिल, ऋणशोधनाक्षमता बिल, दिवालियापन बिल, आदि। श्रम कोड को भारतीय संसद ने पास कर दिया है परंतु देश में लागू किया जाना शेष है, कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण बिल पर कार्य चालू है। ईज आफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है और आज विभिन्न प्राजेक्ट्स को समय पर स्वीकृती मिल जाती है। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित अवस्था में आ चुका है। भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में से निकालकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ले आया गया है। फिर भी, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल 7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर काफी नहीं है।

वर्ष 2023–24 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2 प्रतिशत की रही है और प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,300 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तभी शामिल किया जाता है जब उस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 13,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष के आस पास हो। इस दृष्टि से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय नागरिकों की औसत आय लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़नी चाहिए। इस प्रकार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद भी यदि 8 प्रतिशत के आसपास प्रतिवर्ष बढ़ता है तो वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र निश्चित ही बन सकता है। परंतु इसके लिए भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को और अधिक गति देनी होगी।

वर्तमान में केंद्र सरकार 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हाल ही के वर्षों में लागू किए गए सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं – वस्तु एवं सेवा कर बिल, ऋणशोधनाक्षमता बिल, दिवालियापन बिल, आदि।

आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लम्बे समय तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कई बार तो सुधार कार्यक्रम सम्बंधी कानून बनाने के बाद उन्हें लागू करने में भी लम्बा समय लग जाता है। जैसे भारत में 4 श्रम कोड वर्ष 2019–2020 के बीच में संसद द्वारा पास किए गए थे परंतु इन कोड को अभी भी लागू नहीं किया जा सका है। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में काम किया जाना शेष है। जैसे, भारत में पूंजी आज भी बहुत अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो पाती है, हालांकि ऋण प्रदान करने सम्बंधी नियमों को शिथिल बनाया गया है, परंतु पूंजी की लागत बहुत अधिक है। भारत में युवा जनसंख्या अच्छी तादाद में है, आज भारत के नागरिकों की औसत आयु केवल 29 वर्ष है जो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। यह भारत के लिए यह लाभदायक स्थिति है परंतु भारत आज भी इस स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस प्रकार के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर भारत में अभी भी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है।

भारत को अभी भी आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे देश की मजबूती किन क्षेत्रों में हैं इन क्षेत्रों को चिन्हित कर हमें उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे उत्पादकता के मामले में अन्य देशों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों, की तुलना में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। उत्पादकता कम होने के चलते भारत में निर्मित उत्पादों की लागत अधिक रहती है। देश में करों की दर (प्रत्यक्ष एवं

भारत की आर्थिक विकास दर को १० प्रतिशत से भी ऊपर ले जाया जा सकता है यदि हिंदू सनातन संस्कृति की अर्थव्यवस्था को भारत में बढ़ावा दिया जाये। इसके लिए देश के ब्यूरोक्रेसी के सोच में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण कर एवं इन स्थानों पर अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए धार्मिक पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा सकता है।

अप्रत्यक्ष) अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, इसे कम करने के सम्बंध में गम्भीरता से विचार करने की आज महती आवश्यकता है। साथ ही, बैकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋण पर ब्याज की दर भी बहुत अधिक है, इससे भी उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और भारत में निर्मित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक लागत के चलते टिक नहीं पाते हैं। अतः अब समय आ गया है कि ब्याज दरों को कम करने के बारे में भी गम्भीरता से विचार हो।

देश में हर समय कहीं न कहीं चुनाव हो रहे होते हैं और कई बार तो देश के बहुत बड़े भू भाग पर चुनाव आचार संहिता के लागू होने के चलते केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत खर्चे रोकने होते हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः देश में वन नेशन वन इलेक्शन को भी लागू करने की महती आवश्यकता है। साथ ही, आजकल कुछ राज्य सरकारों के बीच नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जैसे होड़ ही लग गई है। मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने से इन प्रदेशों के बजट पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। अतः इस प्रकार के खर्चों पर रोक लगाए जाने की भी आज आवश्यकता है।

भारत की आर्थिक विकास दर को 10 प्रतिशत से भी ऊपर ले जाया जा सकता है यदि हिंदू सनातन संस्कृति की अर्थव्यवस्था को भारत में बढ़ावा दिया जाय। इसके लिए देश के ब्यूरोक्रेसी के सोच में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण कर एवं इन स्थानों पर अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए धार्मिक पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे होटल उद्योग, परिवहन उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बहुत लाभ होगा एवं रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी निर्मित होंगे। देश में शादियों के मौसम में लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता है तथा विभिन्न त्यौहारों पर भी भारतीय नागरिकों के खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस सबका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रहता है, अतः शादियों के मौसम एवं विभिन्न त्यौहारों पर नागरिकों को सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान करने से विभिन्न उत्पादों की खपत में वृद्धि की जा सकती है। और, अंततः यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने में सहायक होगा। अतः हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों को देश में लागू करने के संदर्भ में अब देश के ब्यूरोक्रेसी को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

आज अतीत के बोझ को छोड़कर भविष्य की तरफ देखने की भी आवश्यकता है और देश के आर्थिक विकास के लिए नित नए क्षेत्रों की तलाश भी जारी रखनी होगी।

हाल के समय में देश में बचत एवं निवेश दर में कमी देखी जा रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी कमी दृष्टिगोचर हुई है और विदेशी व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि देश में स्वर्ण एवं कच्चे तेल का आयात अत्यधिक मात्रा में हो रहा है और विभिन्न उत्पादों का निर्यात उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। स्वर्ण के आयात को तो नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि यह किसी भी प्रकार की उत्पादकता अथवा लाभ अर्जन में भागीदारी नहीं करता है बल्कि यह निवेश निष्क्रिय निवेश की श्रेणी में गिना जाता है। स्वर्ण में निवेश की जा रही विदेशी मुद्रा को यदि विनिर्माण इकाईयों की स्थापना पर खर्च किया जाय तो यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने में सहायक होगा।

किसी भी विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए विशेष रूप से 6 घटकों की आवश्यकता होती है यथा – भूमि, पूंजी, श्रम, नई तकनीकी, संगठन एवं साहस। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार नौकरी को निकृष्ट कार्य की श्रेणी में गिना जाता रहा है एवं अपना उद्यम चलाना उच्च कार्य माना जाता है। अतः संगठन क्षमता एवं साहस भारत के मूल नागरिकों के डीएनए में है। नई तकनीकी को विकसित करने में भारत के युवा इंजीनीयरों ने पूरे विश्व को राह दिखाई है। अतः भारत में केवल भूमि, पूंजी एवं श्रम की लागत को कम करने में यदि सफलता हासिल की जा सके तो भारत की आर्थिक विकास दर को 10 प्रतिशत से भी ऊपर ले जाया जा सकता है। भूमि, पूंजी एवं श्रम जहां भी आसानी से एवं उचित दामों पर उपलब्ध होंगे वहां उद्योग धंधे आसानी से फलेंगे एवं फूलेंगे। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी की कलम से।)

अद्भुत अलौकिक अपूर्व - महाकुंभ

वर्तमान में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और महाकुंभ में स्नान करने की एक होड़ सी लगी है कि कैसे भी हो, महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य हाथ से निकल न जाये और फिर 144 वर्ष की प्रतीक्षा के लिए कितने जन्म लेने पड़ें!! अभी तक लगभग 50 करोड़ सनातनी महाकुंभ में स्नान कर चुके और अभी 13 दिन शेष हैं और दो महास्नान भी शेष हैं। पहले भी कुंभ और महाकुंभ हमारे ही जीवन काल में आयोजित हुए हैं, परंतु जो संयोग, उत्साह, उमंग, साहस, लक्ष्य निष्ठता और प्रण इस बार है, उससे महाकुंभ में स्नान करके यह जीवन धन्य हो गया। विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया, निजी मिलन, चाय की दुकानों, नुक्कड़, प्रातः पार्कों में, घरों–परिवारों में महाकुंभ की जितनी चर्चा और उत्साह है, वह अभूतपूर्व है।

आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है "महाकुम्भ"। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुम्भ मेले का वो आयाम है जो आदि काल से ही हिन्दू धर्मावलम्बियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमन्त्रण के खींच कर ले आता है। कुम्भ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ था, अपितु इसका इतिहास समय के प्रवाह से साथ स्वयं ही बनता चला गया। वैसे भी धार्मिक परम्पराएं हमेशा आस्था एवं विश्वास के आधार पर टिकती हैं न कि इतिहास पर। यह कहा जा सकता है कि महाकुम्भ जैसा विशालतम् मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है।

कुंभ जैसी एकता कहीं नहीं मिलेगी। यहां कोई नहीं पूछता कि कौन किस जाति भाषा प्रांत से है। सब जुटे हैं। साधु–संत सवारी निकाल रहे हैं। कोटि–कोटि जन स्नान कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी एकता है। धन्य है भारत की भूमि जहां तीन पावन नदियों की धारा (संगम) आपस में मिलकर हम सबको मिलना सिखा रही हैं।

परमात्मा ने भी जगत का कुंभ बनाया है। जगत रूपी चाक बनाकर कुंभ की रचना करते हैं। समुद्र मंथन से निकले अमृत कुंभ की बूंदें चार स्थानों पर जहां भी गिरी हैं, वहां अमृत होने का बोध होता है। महाकुंभ में अमृत पान के लिए लोग आ रहे हैं।

– विनोद जौहरी

ज्योतिष गणना के क्रम में कुम्भ का आयोजन चार प्रकार से माना गया है –

1. बृहस्पति के कुम्भ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा–तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।
2. बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चन्द्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।
3. बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।
4. बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में शिप्रा तट पर कुम्भ पर्व का आयोजन होता है।

धार्मिकता एवं ग्रह–दशा के साथ–साथ कुम्भ पर्व को तत्त्वमीमांसा की कसौटी पर भी कसा जा सकता है, जिससे कुम्भ की उपयोगिता सिद्ध होती है। कुम्भ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह पर्व प्रकृति एवं जीव तत्त्व में सामंजस्य स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों को समाविष्ट करता है। प्रकृति ही जीवन एवं मृत्यु का आधार है, ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति–आवश्यक हो जाता है। कहा भी गया है "यद् पिण्डे तद्

ब्रह्माण्डे" अर्थात् जो शरीर में है, वही ब्रह्माण्ड में है, इस लिए ब्रह्माण्ड की शक्तियों के साथ पिण्ड (शरीर) कैसे सामंजस्य स्थापित करे, उसे जीवनदायी शक्तियाँ कैसे मिले, इसी रहस्य का पर्व है कुम्भ। विभिन्न मतों–अभिमतों–मतान्तरों के व्यावहारिक मंथन का पर्व है–'कुम्भ', और इस मंथन से निकलने वाला ज्ञान–अमृत ही कुम्भ–पर्व का प्रसाद है ।

कुंभ के कई अर्थ हैं, लेकिन प्रचलित कथा तो यही है कि समुद्र मंथन से अमृत कुंभ निकला। कुंभ से जहां–जहां वह छलका, वहां हम 12 साल में पूर्ण कुंभ मनाते हैं। कुंभ महामिलन है, महासम्मेलन है। कुंभ (घड़े) को देखें, तो उसका उदर बड़ा है और मुख संकीर्ण है। इसका अर्थ है कि जो कहना है, वह लघु रूप से सूत्र रूप में कह देता है, यद्यपि उसके उदर में तो सब शास्त्र होते हैं। इतना उदार उसका पेट है।

हर मांगलिक कार्य में, पूजा में कलश की स्थापना होती है। मंत्र भी ऐसे हैं कि कलश के मूल में यह देवता, मध्य में यह देवता, मुख्य में यह देवता वास करते हैं। हमारी प्रवाही परंपरा में कुंभ की बड़ी महिमा है। हम पूरी गंगा को घर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन कुंभ में भरकर गंगा को घर में ला सकते हैं।

कुंभ में सब आए हैं, लेकिन स्पर्धा करने के लिए नहीं, त्रिवेणी में स्थान करने के लिए। कुंभ जैसी एकता कहीं नहीं मिलेगी। यहां कोई नहीं पूछता कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन किस जाति का है। किस भाषा, प्रांत, वर्ण से है। सब जुटे हैं, बिना कोई नेटवर्क बनाए। साधु–संत सब अपने हिसाब से सवारी निकाल रहे हैं। कोटि–कोटि जन स्नान कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी एकता है। धन्य है भारत की भूमि, जहां तीन पावन नदियों की धारा आपस में मिलकर हम सबको मिलना सिखा रही हैं।

कुंभ में लोग कुछ लेने नहीं, बल्कि देने आते हैं। हां, पुण्य कमाने की इच्छा होती है, लेकिन मीलों नंगे पांव चलकर अपनी पवित्र परंपरा का दर्शन करने वे आते हैं। कुंभ विशेष भूमि पर होता है। यह विशेष महिमा वाली भूमि है। हम कहीं भी कथा करते हैं तो पहले तीन–चार दिन वायुमंडल बनाना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुंभ में बना–बनाया वातावरण मिलता है। हजारों वर्षों का पुण्य यहां जमा है। कुंभ में किसी महात्मा से मिलना, कल्पवास कर रहे लोगों के दर्शन करना, बहुत महिमा का काम है। कौन क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इनमें कुछ प्रत्यक्ष चेतना हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष चेतना हैं। हम किसी चेतना को न देख पाएं, न पहचान पाएं, लेकिन वह हमें देख ले तो यह भी हमारा गंगा स्नान है। दर्शन, स्नान, स्पर्श, पान की महिमा है। साथ ही स्मरण की भी महिमा है।

युवा बहुत अधिक संख्या में कुंभ से जुड़ रहे हैं। कुंभ की चेतना सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसा और भी अच्छा दर्शन हो सकता है। कुंभ और तीर्थ दिव्य ही हैं। कुंभ भव्यता से भरा है, लेकिन मूल में दिव्यता है। आज का विज्ञान भव्यता बना रहा है, लेकिन कुंभ दिव्य तो है ही। इस बार एक विशेषता यह भी है कि इतने वर्षों के बाद ग्रह–नक्षत्र एक साथ अनुकूल हुए हैं।

इस महाकुंभ का संदेश है कि व्यक्ति–व्यक्ति, परिवार–परिवार, समाज–समाज, भाषा–भाषा, वर्ण–वर्ण, जाति–जाति, देश– दुनिया सबके बीच में वैचारिक संगम हो। बौद्धिक और हार्दिक संगम हो। हमारे चिंतन का केंद्र बिंदु संगम है। यह महाकुंभ, इतने वर्षों के बाद हुआ है। इसलिए इस बार की कथा का नामकरण भी मानस महाकुंभ किया गया।

रामचरित मानस भी एक महाकुंभ है, जो निरंतर अंतरस्नान और अवगाहन कराता है। इसका दर्शन, इसका स्पर्श, इसका आचमन, इसका निमज्जन चारों रूपों का रामचरित मानस की पंक्ति में वर्णन आता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी स्थावर संगम और राम चरित मानस जंगम संगम है। दुनियाभर में प्रयागराज घूम रहा है।

परमात्मा ने भी जगत का कुंभ बनाया है। जगत रूपी चाक बनाकर कुंभ की रचना करते हैं। समुद्र मंथन से निकले अमृत कुंभ की बूंदें चार स्थानों पर जहां भी गिरी हैं, वहां अमृत होने का बोध होता है। महाकुंभ में अमृत पान के लिए लोग आ रहे हैं। इस कुंभ का चिंतन अनेक रूपों में किया गया है। कुंभ से ही कुंभज (अगस्त्य ऋषि) रामकथा लेकर उत्पन्न हुए थे। ❑❑

संदर्भ – स्वयं का अनुभव, महाकुंभ की वेबसाइट, दैनिक जागरण (11 फ़रवरी परमादरणीय मोरारी बापू का लेख – समस्त वेद शास्त्र–शास्त्रों का सत्व–तत्व है कुंभ)

साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण आवश्यक

प्रतिवर्ष 2 फरवरी को 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस'(वर्ल्ड वैटलैंड डे) पर्यावरण में आर्द्रभूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वास्तव में, यह दिवस धरती पर जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी), जलवायु और जल विनियमन के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के क्रम में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि वेटलैंड्स वाटरशेड की पारिस्थितिकी में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं।

जानकारी के अनुसार उथला पानी उच्च स्तर के पोषक तत्त्वों का संयोजन जीवों के विकास के लिये आदर्श है जो खाद्य वेब का आधार बनाते हैं और मछली, उभयचर, शंख व कीड़ों की कई प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। वास्तव में,दलदली भूमि, बाढ़ के मैदान, नदियां, झीलें, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां और अन्य समुद्री क्षेत्र जो कि कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे न हो– सब वेटलैंड्स की श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, मानव निर्मित तालाब या अपशिष्ट–जल को उपचारित करने वाले तालाब या जलाशय भी इसमें शामिल हैं। सच तो यह है कि वेटलैंड्स की जैविक संरचना में पानी में रहने वाली मछलियां, पानी के आसपास रहने वाले प्रवासी पक्षी सब शामिल हैं।

ज्ञात हो कि आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। यदि हम वैटलैंड की परिभाषा की यहां बात करें तो 'स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहाँ जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है।' सरल शब्दों में कहें तो आर्द्रभूमि (वैटलैंड) ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थाई रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त (सचुरेटेड) हो या उसमें डूबा रहे। आर्द्रभूमियों

प्राकृतिक संसाधनों के बेहताशा दोहन से भी आज जलीय जीवन लगातार खतरे में है। संविधान के मुताबिक पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह चाहिए कि हम जंगल, वन्यजीव, नदी और झील और वैटलैंड सबको बचाएं।

– सुनील कुमार महला

में क्रमशः तटीय आर्द्रभूमियों, उथली झीलों और तालाबों, दलदल, स्वैंप्स, बॉग्स और मुहानों को शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि वर्तमान में विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

यदि हम यहां भारत की बात करें तो फरवरी 2022 तक भारत में 49 रामसर स्थलों का एक नेटवर्क है। यह 10,93,636 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 4.6 प्रतिशत भूमि आर्द्रभूमि के रूप में है, जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। गौरतलब है कि भारत में आर्द्रभूमि ठंडे एवं शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों तथा दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदान से लेकर समुद्र किनारे मैंग्रोव तक, भांति–भांति प्रकार के वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। यह भी गौरतलब है कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समर्पित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया था, जिसने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के लिए मंच तैयार किया और पहली बार वर्ष 1997 में यह मनाया गया था।

'विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025' का विषय या थीम 'हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण' रखी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले साल यानी कि वर्ष 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम 'आर्द्रभूमि और मानव कल्याण' रखी गई थी। यह विषय मानव कल्याण के लिए इन प्राकृतिक आवासों की रक्षा हेतु साहसिक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि भावी पीढ़ियां आर्द्रभूमियों से लाभ उठा सकें। उल्लेखनीय है कि मानव कल्याण के सभी पहलू जैसे कि

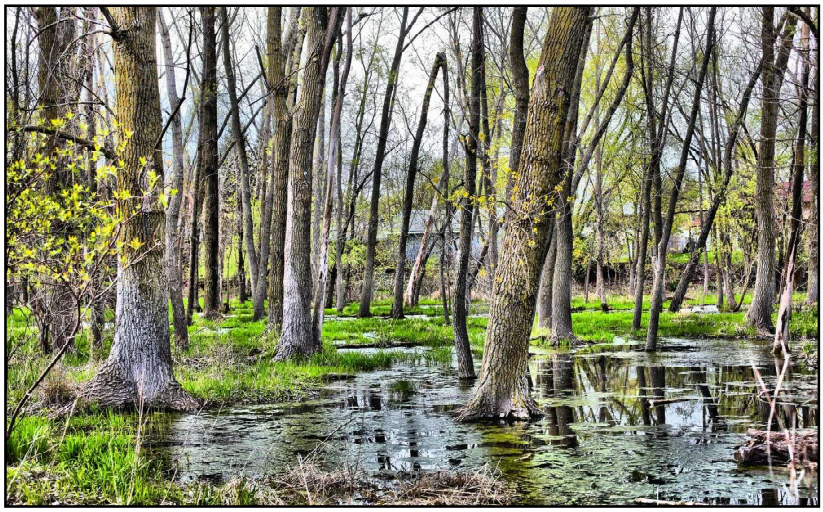

विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जहां एक ओर आर्द्रभूमि के महत्व पर प्रकाश डालता है और दुनिया भर में उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, वहीं पर दूसरी ओर यह दिवस वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए विश्व के विभिन्न देशों को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण व अहम् भूमिका निभाता है।

शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय कहीं न कहीं आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं।

आज संपूर्ण विश्व में जैव–विविधता, जलवायु और जल विनियमन के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की रक्षा और इसे पुनर्स्थापित (रि–एस्टेबिलिस) करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का घर हैं और जल शुद्धिकरण और बाढ़ नियंत्रण जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाएं (इकोलॉजी सर्विसेज) प्रदान करती है विश्व वेटलैंड दिवस धरती पर मानव को इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और रख–रखाव के लिए प्रोत्साहित करता है और शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

आज बदल रही जलवायवीय परिस्थितियों के बीच आर्द्रभूमियों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक व जरूरी हो गया है। यह दिवस जहां एक ओर आर्द्रभूमि के महत्व पर प्रकाश डालता है और दुनिया भर में उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, वहीं पर दूसरी ओर यह दिवस वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए विश्व के विभिन्न देशों को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण व अहम् भूमिका निभाता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज धरती पर बढ़ते प्रदूषण यथा वायु, जल, मृदा से आर्द्रभूमियां लगातार प्रभावित होती चली जा रही है और इससे जैव–विविधता पर भी व्यापक असर पड़ रहा है।

वर्ल्ड वैटलैंड डे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से निपटने की आवश्यकता पर विशेष जोर देता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि यह पर्यावरणीय महत्व पर विशेष ध्यान केंद्रित करके, विश्व समुदायों और सरकारों को आर्द्रभूमि संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

आर्द्रभूमि पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही नहीं, यह जल शुद्धिकरण और हमारी धरती की पारिस्थितिकी को भी संतुलित करती हैं। आर्द्रभूमियाँ बाढ़, सूखे और तूफान के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करती हैं। वे कार्बन की भारी मात्रा संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। आर्द्रभूमियाँ सांस्कृतिक, मनोरंजक और सौंदर्य मूल्यों में योगदान करती हैं।

ध्यातव्य हो कि आर्द्रभूमि पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही नहीं, यह जल शुद्धिकरण और हमारी धरती की पारिस्थितिकी को भी संतुलित करती हैं। आर्द्रभूमियाँ बाढ़, सूखे और तूफान के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करती हैं। वे कार्बन की भारी मात्रा संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। आर्द्रभूमियाँ सांस्कृतिक, मनोरंजक और सौंदर्य मूल्यों में योगदान करती हैं। बहुत कम लोगों को ही यह जानकारी होगी कि वेटलैंड्स अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं जो दुनिया को मत्स्य उत्पादन का लगभग दो–तिहाई हिस्सा प्रदान करते हैं।

उल्लेखनीय है कि जैव–विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्रभूमि पर उगने और फलने–फूलने के लिये अनुकूलित होते हैं। एक जानकारी के अनुसार आर्द्रभूमि के जीवाणु, पौधे व वन्यजीव, पानी, नाइट्रोजन और सल्फर के वैश्विक चक्रों का हिस्सा हैं। आर्द्रभूमि कार्बन को अपने पादप समुदायों व मिट्टी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय संग्रहीत करती है। वैटलैंड जानवरों और पौधों के लिये आवास प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, आर्द्रभूमियाँ सतही जल, वर्षा, भूजल और बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और धीरे–धीरे इसे फिर से पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ती है और इस तरह से वैटलैंड एक 'नैचुरल बैरियर' की भूमिका का निर्वहन करती है।

आर्द्रभूमि (वैटलैंड) में पैदा होने वाली वनस्पतियां बाढ़ के पानी की गति को भी धीमा कर देती है, जिससे मिट्टी के कटाव (मृदा अपरदन) में कमी आती है। तात्पर्य यह है कि यह बाढ़ जैसी आपदा को रोकने में सहायक या मददगार साबित होती है। आर्द्रभूमियां न केवल मानव बल्कि जीव–जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में तो इनकी भूमिका है ही।

एक आंकड़े के अनुसार एक अरब से अधिक लोग जीवन यापन के लिये वैटलैंड्स पर निर्भर हैं और दुनिया की 40 प्रतिशत प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में निवास एवं प्रजनन करती हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आर्द्रभूमि बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव–विविधता और मनोरंजन के अवसरों,परिवहन, पर्यटन(जैसा कि वैटलैंड प्राकृतिक सुन्दरता के क्षेत्र होते हैं) और लोगों की सांस्कृतिक संरक्षण एवं आध्यात्मिकता में योगदान करती हैं, जो मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक व जरूरी हैं। वैटलैंड आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं क्यों ये क्षेत्र उन्हें जीने के लिए बहुत सी चीजें प्रदान करते हैं यथा कच्चा माल(रा मैटिरियल) मछलियां, पानी, जड़ी–बूटियां आदि।

वस्तुतः वेटलैंड्स धरती के लिए गुर्दे का काम करते हैं, क्यों कि ये गंदे पानी को स्वच्छ पानी में तब्दील करने की क्षमताएं रखते हैं।सच तो यह है कि जल–चक्र को बनाए रखने के लिए वेटलैंड्स का काफी महत्व है। जल संग्रहण, भूजल स्तर को बनाए रखने और पानी की सफाई तक में इसकी भूमिका है। बाढ़ का पानी अपने में समटेकर यह हमें बाढ़ से बचाने में बहुत ही मददगार है। मौसम परिवर्तन की घटनाएं जैसे बाढ़ और सूखे से निपटने में कई वेटलैंड्स सहायक हैं। आंकड़े बताते हैं कि आज विश्व भर के 87 प्रतिशत वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। वर्ष 1970 के बाद दुनिया के 35 प्रतिशत वेटलैंड्स खत्म हो गए। भारत में एक तिहाई वेटलैंड्स शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार, बढ़ती जनसंख्या की भेंट चढ़ गए।

आज शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में शहरों के आसपास या शहरों में ही कचरे के ढेर पहाड़ जैसे बनते जा रहे हैं, जिससे वेटलैंड्स के पाटे जाने का खतरा बना रहता है। कई जलस्रोत अपशिष्ट जल के भरने की वजह से तबाह हो गए। प्राकृतिक संसाधनों के बेजा दोहन से भी आज जलीय जीवन लगातार खतरे में है। संविधान के मुताबिक पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह चाहिए कि हम जंगल, वन्यजीव, नदी और झील और वैटलैंड सबको बचाएं। ❑❑

(फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड)

उपग्रह प्रक्षेपण से बढ़ता प्रदूषण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष अन्वेषण एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसने मानव जाति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राकेट प्रक्षेपण के माध्यम से उपग्रह और अन्य उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजना आज के युग की आवश्यकता बन गई है। चाहे यह संचार के लिए हो, मौसम का अध्ययन हो ग्रहों पर जीवन की खोज हो, राकेट प्रक्षेपण ने मानवता को नई संभावनाओं से परिचित कराया है। हालांकि इसके साथ ही यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं भी पैदा करती है। प्रक्षेपण के दौरान वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ध्वनि प्रदूषण, जल और मिट्टी का प्रदूषण और अंतरिक्ष में मलबा जैसी समस्याएं अब सामने आ रही हैं। इनको समझना और उनका समाधान निकालना आवश्यक है, ताकि तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

राकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत शक्तिशाली ईंधन का उपयोग किया जाता है। यह ईंधन जलता है, तो बड़ी मात्रा में गैसें और कण उत्सर्जित होते हैं। इनमें कार्बन डाइआक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें शामिल होती हैं। ठोस ईंधन के जलने पर कार्बन और नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित होते हैं, जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। तरल हाइड्रोजन और आक्सीजन उपयोग करने वाले राकेट कम प्रदूषण करते हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह साफ नहीं हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों (यूवी) को अवशोषित करती है, जो मानव, जीव–जंतुओं और पौधों के और पौधों के लिए घातक होती हैं। इसे पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह है, हमारे ग्रह ग्रह को प्राकृतिक आपदाओं और जैविक क्षति से बचाती है। राकेट प्रक्षेपण के दौरान ठोस 'प्रोपेलेंट्स' में उपयोग किए जाने वाले क्लोरिन–आधारित यौगिक ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। क्लोरीन अणु ओजोन अणुओं को तोड़ कर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं, जो स्वास्थ्य और। और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। राकेट प्रक्षेपण के दौरान नाइट्रोजन आक्साइड गैसें पैदा होती हैं, जो ओजोन

राकेट प्रक्षेपण आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की रीढ़ है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रक्षेपण से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं।

– विजय गर्ग

के साथ प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट करती हैं। ये गैसें कई वर्षों तक वर्षा तक वायुमंडल में बनी रह सकती हैं। प्रक्षेपण के दौरान निकली गैसें सीधे ऊपरी वायुमंडल प्रवेश करती हैं, जहां ओजोन परत को खुद को पुनर्निर्मित करने का समय नहीं मिलता। बार–बार प्रक्षेपण से यह समस्या और बढ़ जाती है। ठोस और तरल ईंधनों के जलने से कालिख और ब्लैक कार्बन कण पैदा होते हैं, जो ओजोन परत के परत के नवीकरण को रोकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में वृद्धि के कारण राकेट प्रक्षेपण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह ओजोन परत के लिए दीर्घकालिक खतरा है।

राकेट प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न ध्वनि का स्तर अधिक होता है, जो मानव और वन्यजीवों दोनों के लिए हानिकारक है। यह स्थानीय पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालता है और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को बाधित करता है। प्रक्षेपण स्थल के आसपास के जानवर और पक्षी तीव्र ध्वनि से भयभीत हो जाते हैं, जिससे उनके व्यवहार और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता के कारण आसपास के पेड़ों और वनस्पतियों को भी नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ध्वनि हानिकारक होती है। यह सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रक्षेपण स्थल पर मौजूद लोगों को मानसिक तनाव, अनिद्रा और अन्य शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि तरंगें आसपास की इमारतों और संरचनाओं को क्षति पहुंचा सकती हैं।

जब राकेट उड़ान भरता है, तो उसका इंजन बहुत अधिक गर्मी और गैस उत्सर्जित करता है, जिसमें हानिकारक रसायन और भारी धातुएं होती हैं। ये रसायन जमीन पर गिर कर मिट्टी में मिल जाते हैं। जिससे उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। राकेट ईंधन में मौजूद हानिकारक रसायन (जैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भारी धातुएं) मिट्टी की संरचना को बदल देते हैं। इन रसायनों के कारण मिट्टी का पीएच स्तर असंतुलित हो सकता है, जिससे वहां की खेती और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। प्रदूषित मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और कीड़ों के जीवित रहने में कठिनाई । होती है, जिससे जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है। इन रसायनों का असर मिट्टी पर लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। वहीं प्रक्षेपण से अंतरिक्ष मलबे का बनना एक बड़ी समस्या जब कोई राकेट अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो उसके अलग–अलग हिस्से जैसे बस्टर जसे बूस्टर और उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अन्य उपकरण, अपने काम पूरे करने के बाद अलग हो। इनमें से कुछ पृथ्वी पर वापस गिरते हैं, लेकिन कई टुकड़े अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं। पुराने और निष्क्रिय उपग्रह समय के साथ टूटने लगते हैं, जिससे छोटे–छोटे टुकड़े बन जाते हैं। जब दो उपग्रह या मलबे आपस में टकराते हैं, तो उनके टुकड़े और ज्यादा मलबा बनाते हैं।

राकेट और उपग्रह भेजने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम और दिशा–निर्देश बनाए गए हैं, ताकि मलबे की समस्या को नियंत्रित किया सके। प्रक्षेपण स्थल के चारों ओर ध्वनि अवरोधक बनाए जा सकते हैं। राकेट प्रक्षेपण के दौरान जलवाष्प का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है। यह तरीका नासा और अन्य एजेंसियां अपनाती हैं। क्लोरीन आधारित ठोस ईंधनों को नाइट्रोजन आधारित यौगिकों से प्रतिस्थापित करना ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है।

वैज्ञानिकों ने कई नवाचार किए। जिनका उद्देश्य प्रक्षेपण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। हरित ईंधन के विकास और उपयोग से प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जैव ईंधन, तरल हाइड्रोजन और तरल आक्सीजन जैसे ईंधन न केवल कम विषैले होते हैं, बल्कि इनके जलने से न्यूनतम प्रदूषण होता है। राकेट प्रक्षेपण स्थलों को ऐसे क्षेत्रों स्थापित किया जाए, जहां पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, जैसे समुद्र तट के नजदीक। संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से प्रक्षेपण स्थलों को दूर रखना चाहिए। स्पेसएक्स जैसे संगठनों ने पुनः उपयोग योग्य राकेट विकसित किए हैं, जैसे फाल्कन 9, यह तकनीक हर प्रक्षेपण के लिए नए राकेट की जरूरत को समाप्त करती है।

राकेट प्रक्षेपण आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की रीढ़ है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रक्षेपण से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, जल और मिट्टी का प्रदूषण और अंतरिक्ष मलबा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें तकनीकी नवाचार, नीति निर्माण और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। नवीन प्रौद्योगिकियां, जैसे– उपयोग योग्य राकेट और और 'ग्रीन प्रोपेलेंट्स' तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए क्रांतिकारी कदम हैं। स्पेसएक्स, नासा, और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियमों का पालन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी देश पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व को समझें और उनका अनुपालन करें। आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। ❑❑

(सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब)

गंगा का विज्ञानः प्राचीन ज्ञान और आधुनिक खोज का संगम

गंगा नदी सदियों से श्रद्धा, रहस्य, और चमत्कारों से घिरी है। लोग अक्सर इसके पवित्र जल को सामान्य समझ से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी शाश्वत शुद्धता को जानने के लिए विज्ञान, आध्यात्मिकता, और सनातन ज्ञान के साथ गहराई से जुड़ना होगा। आज, एआई जैसे उपकरणों की मदद से हम और गहन प्रश्न पूछ सकते हैं – गंगा के जल को स्वच्छ रखने वाले विशेष जीवाणु कौन से हैं? यह जल अन्य नदियों की तुलना में अधिक समय तक पीने योग्य क्यों रहता है? ये सुपरहीरो जीवाणु अन्य स्थानों पर क्यों नहीं मिलते? इन प्रश्नों के उत्तर सामान्य तर्क से परे हैं और एक ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जो आधुनिक पूर्वाग्रहों के पीछे छिपी रह जाती है।

गंगा के जल का वैज्ञानिक विश्लेषण

विशेष जीवाणु और स्वयं शुद्धिकरणः गंगा के जल में विशेष प्रकार के बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ये बैक्टीरियोफाज जीवाणुओं के प्राकृतिक शिकारी होते हैं और जल को रोगाणुरहित बनाए रखते हैं। सीएसआईआर–नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि गंगा जल में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफाज अन्य नदियों की तुलना में अधिक सक्रिय और विविध होते हैं, जो इसे स्वाभाविक रूप से शुद्ध रखते हैं। इसके अलावा, डॉ. डी.एस. भार्गव द्वारा किए गए शोध में यह प्रमाणित हुआ कि गंगा जल में बायो ऑक्सीडेशन की क्षमता अत्यधिक है, जिससे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है और हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यह गुण अन्य नदियों में दुर्लभ है, जिससे गंगा का जल अधिक समय तक ताज़ा और पीने योग्य रहता है।

ऑक्सीजन की उच्च मात्रा और शुद्धता

गंगा के जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अन्य नदियों की तुलना में अधिक पाई

गंगा का जल केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। यह विज्ञान और आध्यात्म का अद्वितीय संगम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है।

– सचिन अवस्थी

गई है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार, गंगा के पानी में 12 पीपीएम (पार्टस् पर मिलियन) तक घुलित ऑक्सीजन पाई गई, जबकि सामान्यतः अन्य नदियों में यह 8 पीपीएम से कम होती है। यह उच्च ऑक्सीजन स्तर जल में जीवन को बनाए रखने और रोगाणुरोधी गुणों को प्रोत्साहित करने में सहायक है। ऑक्सीजन की इस उच्च मात्रा का कारण हिमालय की गोद से मिलने वाला खनिज युक्त जल है, जो जल के पीएच स्तर को स्थिर और बैक्टीरिया–विरोधी बनाता है। इसके अलावा, गंगा के प्रवाह में वेग और उथल–पुथल भी ऑक्सीजन को जल में घुलने में सहायता करते हैं, जिससे इसका शुद्धता स्तर बरकरार रहता है।

औपनिवेशिक मानसिकता का अंधकार

गंगा के लिए वास्तविक खतरा उसमें स्नान करने वाले करोड़ों लोग नहीं, बल्कि वह सोच है जो भारतीय ज्ञान को नकारकर पश्चिमी व्यावसायिक प्रचारों को अंधविश्वास से मान लेती है। विडंबना यह हैः लोग टॉयलेट क्लीनर के समान अम्लता वाले पेय पदार्थों को विज्ञापनों के कारण पी लेते हैं, पर गंगा की पवित्रता पर संदेह करते हैं। यह केवल पाखंड नहीं, बल्कि बौद्धिक उपनिवेशवाद है, जो सनातन सत्य को पश्चिमी नजरिए से कम आंकता है।

भारतीय पारंपरिक ज्ञान बनाम पश्चिमी दृष्टिकोण

गंगा के पवित्र जल की वैज्ञानिकता को समझने के लिए भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद और प्राचीन वेदों में गंगा जल को "अमृत" कहा गया है, जो रोगाणुरोधी और आरोग्यकारी गुणों से युक्त है। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है जिसे आधुनिक शोध भी प्रमाणित कर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन–डब्ल्यूएचओ) ने भी माना है कि गंगा जल में पाए जाने वाले कुछ खनिज तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसके अलावा, गंगा के जल में यूरेका नामक सूक्ष्म खनिज पाए गए हैं, जो शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने में सहायक हैं।

नदी नहीं, एक ब्रह्मांडीय चमत्कार

गंगा को केवल एक नदी समझना इसके महत्व को सीमित करना है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अखंड ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया है। आधुनिक विज्ञान भी अब इसकी विशेषताओं जैसे स्वयं शोधक जीवाणु और ऑक्सीजन संचय क्षमता को स्वीकार कर रहा है, जो ऋषियों के दिव्य जल की अवधारणा से मेल खाते हैं। खगोल विज्ञान और क्वांटम भौतिकी जैसे क्षेत्र भी वैदिक सिद्धांतों को दोहरा रहे हैं, हालाँकि उन्हें नवीन अनुसंधान कहा जाता है।

क्वांटम भौतिकी और वैदिक ज्ञान का संगम

आधुनिक क्वांटम भौतिकी यह सिद्ध करती है कि जल में मेमोरी रिटेंशन (स्मरण शक्ति) होती है। जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो के शोध के अनुसार, जल में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने की क्षमता होती है। यह बात भारतीय ऋषियों द्वारा गंगा को "स्मृति दायिनी" कहे जाने से मेल खाती है। गंगा के जल में मंत्रों और यज्ञों द्वारा सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने की परंपरा केवल आस्था नहीं, बल्कि क्वांटम सिद्धांतों से भी प्रमाणित होती है। इसके अलावा, गंगा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करते हैं, जो जीवाणु रोधी और शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। आईआईटी कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किए गए संयुक्त शोध में यह पाया गया कि गंगा जल में सिलिका और सोना जैसे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जो इसे जीवाणु रोधी और स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं।

पुनर्खोज का युग, स्वीकृति का नहीं

भारत के ज्ञान को पश्चिमी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं बस उसे समझने वाले जिज्ञासु मन चाहिए। जब जब आधुनिक विज्ञान प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों को खोज लेता है, तो यह हमें याद दिलाता है कि हमने अपनी विरासत को भुला दिया है। गंगा का रहस्य हमें औपनिवेशिक द्वंद्व से मुक्त होकर विज्ञान और आध्यात्म के सहअस्तित्व को देखने का आह्वान देता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण

गंगा केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है। इसमें पाए जाने वाले नकारात्मक आयन मानसिक तनाव को कम करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह गुण विशेष रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे स्थानों पर अधिक देखा गया है, जहां गंगा उच्च वेग से बहती है। आधुनिक विज्ञान अब यह मान रहा है कि नकारात्मक आयन मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो योग और ध्यान की परंपरा में वर्णित ऊर्जा संतुलन से मेल खाता है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम है।

निष्कर्षः विज्ञान और अध्यात्म का अनूठा संगम

गंगा का जल केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। यह विज्ञान और आध्यात्म का अद्वितीय संगम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। आधुनिक विज्ञान केवल उसकी परतें खोल रहा है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। गंगा हमें याद दिलाती है कि सच्चा विज्ञान वह है जो समय, स्थान, और पूर्वाग्रहों से परे हो। ❑❑

'मन चंगा तो कठौती में गंगा': संत रविदास

महान संत, दर्शनशास्त्री, कवि, समाज–सुधारक और ईश्वर के अनुयायी संत शिरोमणि रविदास के जन्म को लेकर सबकी अपनी–अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1376–77 के आसपास हुआ था, कोई 1399 ई. कुछ दस्तावेजों के अनुसार रविदास 1450 और 1520 के बीच रहे। मान्यता के अनुसार रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के निकट सीर गोवर्धन गांव में हुआ था। उनकी माता कालसा देवी थीं और उनके पिता संतोख दास थे। अलौकिक, संत रविदास भारत में 15 वीं शताब्दी के संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। उन्होंने अपने महान कविता लेखन के जरिए विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। उन्होंने समानता पर जोर दिया जहां प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मानवाधिकारों का आनंद मिलेगा। उनके भक्ति छंद सिख धर्मग्रंथों, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं।

स्तुत्य, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक रविदास ने 120 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में वाराणसी में देहत्याग दिया। रविदास के अनमोल वचन थे कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य है। परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। मोह माया में फंसा जीव भटकता रहता है इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है।

उत्कंठ, संत रविदास की मशहूर कहावत 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' को ज्यादातर लोगों को बोलते हुए सुना होगा। इस कहावत का अर्थ है अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। दरअसल इस कहावत का जन्म उस समय हुआ जब एक बार संत रविदास के कुछ विद्यार्थी और अनुयायी ने पवित्र नदी गंगा में स्नान के लिये पूछा तो उन्होंने ये कह कर मना किया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा कर दिया है तो अब वही उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रविदास जी के एक विद्यार्थी ने उनसे दुबारा निवेदन किया तब उन्होंने कहा उनका मानना है कि " मन चंगा तो कठौती में गंगा " मतलब शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरुरत है ना कि किसी पवित्र नदी में नहाने से, अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र है चाहे हम घर में ही क्यों न नहाये।

वस्तुतः संत रविदास ने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। छुआछूत आदि का उन्होंने विरोध किया और पूरे जीवन इन कुरीतियों के खिलाफ ही काम करते रहे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान बनाया है न कि इंसान ने ईश्वर बनाया है अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान है। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में, संत गुरु रविदास ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। अभिभूत, गुरुजी के अध्यापन से प्रभावित होकर चितौड़ साम्राज्य के राजा, रानी और अनेकानेक जन उनके अनुयायी बनकर भक्ति मार्ग में विलीन हो गए।❑❑

संत रविदास ने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। छुआछूत आदि का उन्होंने विरोध किया और पूरे जीवन इन कुरीतियों के खिलाफ ही काम करते रहे।

– हेमेन्द्र क्षीरसागर

स्वदेशी जागरण मंच ने की बजट पर चर्चा

स्वदेशी जागरण मंच, जोधपुर प्रांत की बजट समीक्षा बैठक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आयोजित की गई। बैठक में जोधपुर प्रांत विचार प्रमुख और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर कृष्ण अवतार गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से ग्रोथ साइकिल मॉडल के द्वारा बजट को प्रदर्शित किया और कहा कि इस बार का बजट का साइकिल पॉजिटिव दिशा की ओर है जिसके द्वारा भारत जल्द ही एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। सोनीपत विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुरेंद्र मोड ने चेतावनी दी कि ग्लोबल वार्मिंग से भारत की कृषि उत्पादन क्षमता में कमी आ सकती है। उन्होंने इस बजट में ग्रीन जॉब्स, ग्रीन इनोवेशन और कार्बन फुटप्रिंट कम करने वाला बजट बताया।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल मित्तल ने कहा कि ने अगले वित्तीय वर्ष से जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा उससे डिमांड बढ़ेगी और सभी क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी। कोटा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मीनू महेश्वरी ने ज्ञान द्वारा इस बजट को गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति को समर्पित बजट बताया।

मेक्सिको के पैन अमेरिका यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर राजेश रंजन ने बताया कि इस बजट में सभी आयामों का ध्यान रखते हुए 2047 तक विकसित भारत के निर्माण को केंद्रित रखकर बजट का निर्माण किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राम प्रहलाद चौधरी ने कहा कि इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में करोड़ रोजगार का सृजन होगा। जयपुर से राजेश कंदोई ने बजट को समावेशी बताया।

प्रोफेसर गुरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि आने वाला बजट देश के इतिहास में मिल का पत्थर सिद्ध होगा और विकसित भारत की ओर बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम बनेगा। बजट समीक्षा बैठक को स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख प्रोफेसर राजकुमार मित्तल और राजस्थान क्षेत्र के स्वावलंबी भारत अभियान के समन्वयक अनिल वर्मा ने भी संबोधित किया। जोधपुर प्रांत के प्रचार प्रमुख मिथिलेश झा ने बताया कि इस ऑनलाइन बैठक में जोधपुर प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रकट किया जिनमें जोधपुर प्रांत के संयोजक प्रमोद पालीवाल, धर्मेश जांगिड़, जितेंद्र मेहरा, हंसराज पवार, श्रवण रायका, रघुवीर, उत्तम कुमार पंचोली, राघव शर्मा, पूनम शर्मा, समुद्र सिंह भगोरा, लोकेंद्र सिंह सुरेंद्र भादू आदि कार्यकर्ता प्रमुख थे।

सरकार का बजट 'दूरदर्शी': स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने केंद्रीय बजट को 'चुनौतियों के बीच दूरदर्शी बजट' करार देते हुए कहा कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी प्रमुख चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।

एसजेएम के सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि यह देश के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों के बीच एक दूरदर्शी बजट है। उन्होंने कहा, ''पिछली दो तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में कमी, रुपये में गिरावट, महंगाई, उपभोग में गिरावट, व्यापार घाटा बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं।''

महाजन ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को समर्थन देना, कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, किसानों को समर्थन देना और कृषि उत्पादन में असंतुलन को दूर करना, दालों और खाद्य तेलों के संबंध में विदेश पर निर्भरता कम करना, मध्यम आय वाले करदाताओं को कर में राहत देना और साथ ही मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं का समाधान करना सरकार के लिए एक ''वास्तविक चुनौती'' था।

उन्होंने कहा, ''बजट 2025–26 में इन सभी चिंताओं का समाधान करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।''

महाजन ने कहा कि बजट ने देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विनिर्माण मिशन, एमएसएमई के लिए बढ़ी हुई ऋण गारंटी, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, पीएलआई का विस्तार और विनिर्माण में सुधार के लिए बजट में प्रस्तावित कई अन्य उपाय ''चीनी प्रभुत्व'' कम करने में देश की मदद करेंगे।

https://hindi.theprint.in/india/rss-affiliated-swadeshi-jagran-manch-calls-budget-visionary/782060/

चुनौतियों के बीच विवेकपूर्ण बजटः डॉ. राजीव कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में महानगर के रामगंगा विहार स्थित टैली इंस्टीट्यूट में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी ने सरकार के बजट पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरूआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव कुमार ने बजट पर विचार रखते हुए कहा इस बार का बजट चुनौतियों के बीच विवेकपूर्ण बजट कहा जा सकता है। सरकार के लिए विनिर्माण विकास को बढ़ावा देना, कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, किसानों का समर्थन करना और कृषि उत्पादन में असंतुलन को दूर करना, दालों और खाद्य तेलों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम करना और मध्यम आय वाले करदाताओं को कर में राहत देना और साथ ही मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को दूर करना बजट 2025–26 की विशेषता रही। मुख्य वक्ता टैली इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सीए अभिनव अग्रवाल केंद्रीय बजट 2025–26 में विकास को बढ़ावा के लिए सरकारी प्रयासों को जारी रखने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया हैं। उन्होंने बताया कि लघु उद्योगों के लिए उत्साहवर्धक योजनाओं से रोजगार सृजन के नए आयाम खुलेंगे।

मनोहरपुर स्थित कृषि संस्थान के प्रमुख डॉ. दीपक मेहंदीरत्ता ने बताया कि सरकार की इच्छा है कि कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाया जाए उसके लिए कृषि में पिछले 100 जिलों के लिए धन–धान्य योजना सरकार ने प्रस्तावित किया है जिसके अंतर्गत 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने पर भी सरकार को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा की कृषि में असीम संभावनाएं हैं, गैर पारंपरिक खेती से किसानों की आय अवश्य बढ़ेगी।

जिला संयोजक हिमांशु मेहरा ने इनकम टैक्स पर बजट की विवेचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में इनकम टैक्स की सीमा में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी है। मध्यम वर्ग के लिए यह निश्चित ही राहत की खबर है। डॉ. नूपुर गुप्ता ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट के प्रभाव का आकलन किया। कार्यक्रम में विभाग महिला प्रमुख अंजू त्रिपाठी, जिला महिला प्रमुख पूनम चौहान, महानगर महिला प्रमुख मीनू अरोड़ा, सह महानगर प्रमुख राजेश खन्ना ने भी अपनी बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा एवं संयोजन स्वावलंबी भारत अभियान के जिला सह समन्वयक सौरभ चौधरी ने किया। अंत में कार्यक्रम अध्यक्ष प्रांत सह संपर्क प्रमुख डॉ. एके अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में एडवोकेट योगेंद्र कुमार चौहान, अभिज्ञान एवं इंस्टीट्यूट के छात्र–छात्रा बड़ी संख्या शामिल रहे।

प्रो. भसीन के संघर्षों का दस्तावेज है 'समर्पण को अर्पण'

प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ प्रचारक व राष्ट्रवादी विचारक प्रो. कैलाश चंद्र भसीन के जीवन संघर्ष व देश के प्रति उनके समर्पण पर आधारित पुस्तक 'समर्पण को अर्पण' का लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन 'किताब वाले' द्वारा किया गया है।

प्रो. कैलाश चंद्र भसीन की पुत्री विपल बत्रा व डॉ. चारू कालरा द्वारा संपादित सात खंड़ों वाली इस पुस्तक में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, संघर्ष व आदशों सहित भारत विभाजन की त्रासदी व कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि यह पुस्तक 82 साल के प्रो. कैलाश चंद्र भसीन पर आधारित है लेकिन फिर भी यह पुस्तक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि घटनाओं का ब्यौरा पेश करती है। यह पुस्तक एक आम व्यक्ति से लेकर ग्रेट थिंकर तक के लिए है।

वहीं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पंजाब केसरी की सीएमडी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन व स्वावलंबी भारत अभियान की मुख्य संरक्षिका किरण चोपड़ा ने कहा कि यह पुस्तक आज के बेटे युवाओं व सभी के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी बेटी ने अपने पिता को यह पुस्तक समर्पित की है। उन्होंने समर्पण को अपर्ण किया है। उन्होंने कहा कि विभाजन की त्रासदी बहुत खतरनाक थी, मेरे परिवार ने भी इस त्रासदी को झेला है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रो. कैलाश चंद्र भसीन के संस्कार चारु कालरा में प्रतिबिंबित होते हैं।

इस दौरान दिल्ली विवि में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. चारु कालरा ने कहा कि पिताजी आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निवर्हन किया। उनके 82वें जन्मदिन पर इस पुस्तक का लोकार्पण हम सभी के लिए एक यादगार क्षण है। पुस्तक में उनकी जीवन यात्रा व संस्मरणों की जानकारी दी गई है ताकि समाज को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। कार्यक्रम में मौजूद गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनीवर्सिटी के वीसी प्रो. महेश वर्मा ने कहा कि हर किसी में समाज को अर्पण करने की क्षमता होती है। अपनी क्षमता के अनुसार हर किसी को कुछ न कुछ समाज को देना चाहिए। इस पुस्तक से भी हम सभी को यही प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम का संचालन सर्जना शर्मा ने किया धन्यवाद ज्ञापन किताब वाले के प्रबंध निदेशक प्रशांत जैन ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष जगदीश मित्तल सहित समाज जीवन के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

स्वदेशी जागरण मंच की बैठक आयोजित

सीतापुर केशव ग्रीन सिटी में अनुपम श्रीवास्तव जी क्षेत्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच का प्रवास हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत स्वदेशी जागरण मंच के संगठन मंत्र से हुई तत्पश्चात अनुपम श्रीवास्तव ने स्वदेशी अपनाओ पर बल दिया तथा घर घर जाकर हर घर स्वदेशी कैसे बनाये, उस पर जोर दिया गया। जिसके मुख्य बिंदु जैसे ईशान कोण में पताका, घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ आदि होना बताया इस अवसर पर मुकेश अग्रवाल जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच सीतापुर द्वारा अनुपम एवं राजीव व सुशील अग्रवाल संरक्षक स्वदेशी जागरण मंच का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

बैठक में उद्यमिता आयोग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रतिबद्ध हुए तथा उद्यमिता आयोग बनने से प्रदेश तथा जिले के सभी व्यापारियों व युवाओं को नए उदयम लगाने में सहयोग व समस्याओं से निजात मिलने के साथ उद्यमिता के माध्यम से बेजोजगारी की समस्या का समाधान होगा। उद्यमिता आयोग बैठक में मोनिका आनंद महिला सशक्तिकरण की सदस्य, मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल स्वदेशी जागरण मंच रामकुमार शुक्ला, मोहित शुक्ला, राकेश यादव, रवि शुक्ला, गुरमीत मौर्य, सुनील बंसल, राजकुमार मौर्य, अमित श्रीवास्तव, सरवन बंसल, रोहित शुक्ला, आलोक मौर्या, राकेश शास्त्री, सुरेश भारती, आशीष बघेल सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

संगमग्राम माधव रेलवे स्टेशन नामकरण की मांग

स्वदेशी जागरण मंच प्रांत समिति की बैठक में मांग की गई कि संगम ग्राम माधव के जन्म स्थान कल्लेट्टुमकारा के रेलवे स्टेशन (इरिंजालाक्कुडा रेलवे स्टेशन) का नाम "संगमग्राम माधव रेलवे स्टेशन" रखा जाना चाहिए। संगम ग्राम माधव जी विश्व प्रसिद्घ गणितीय और खगोलीय शास्त्र प्रतिभा थे। बैठक का उद्घाटन करते हुए स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय समिति के सदस्यण एवं केरल प्रांत के सह –संयोजक श्री.वर्गीस तोडुपराम्बिल ने कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र भेजकर इस अवश्य केलिए कहती है, तो नाम बदलने के कदम बिना देरी के

लागू किए जाएंगे। स्वामी राम प्रसादानंद सरस्वती ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रांत महिला प्रमुख रेखा वरमुद्रा,डॉक्टर. के.ए. फ़िरोज़ खान, अंबिली, पी.प्रसाद, के.जनार्दन नायर, श्यामिली राजेश आदि ने भाषण दिये।

श्री. वर्गीस तोडुपरम्बिलजी पिछले पच्चीस वर्षों से संगम ग्राम माधव आचार्य के योगदान को दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के नाम से वे एक दशक से अधिक समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कल्लेट्टुमकारा उनका भी जन्म ग्राम है। 2022 में अपने प्रवास के दौरान, श्री. अन्नदा शंकर पाणिग्रही जी ने संगमग्राम माधव के जन्मस्थान का दौरा किया। आगे की गतिविधियों के लिए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा सहयोग अपेक्षित है।

अमृतसर में ही बनें आईटी पार्क : डॉ. नेहा सेठी

जिला अमृतसर के नागरिकों की एक पुरानी और महत्वपूर्ण मांग रही है कि अमृतसर शहर व आस–पास के क्षेत्र में एक आधुनिक आईटी पार्क की स्थापना हो। यह न केवल समय की जरूरत है, बल्कि विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

एक आईटी पार्क से यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और व्यवसायों को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। उपरोक्त के बारे डॉक्टर नेहा सेठी 'सह समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच' ने कहा कि वर्तमान में जिला अमृतसर के होनहार युवा करियर की संभावनाओं की कमी के कारण विदेशों का रुख कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई घर वीरान हो गए हैं और माता – पिता अकेलेपन का दर्द सहने को मजबूर हैं।

डॉक्टर सेठी ने कहा कि प्रश्न यह उठता है कि जब बेंगलुरु, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में अत्याधुनिक तकनीकी संरचना हो सकती है, तो अमृतसर इस दौड़ में पीछे क्यों रह जाए? अमृतसर की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्त्व और युवाओं की प्रतिभा इसे एक उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकारों ने इस मुद्दे पर कई वादे किए, लेकिन वे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। सरकारों की निष्क्रियता के कारण शहर की अपार संभावनाएं अभी भी अछूती पड़ी हैं।

बजट 2025 में किसानों को धन–धान्य योजना का तोहफा

निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025–26 में किसान के लिए बड़ा एलान किया है, वित्त मंत्री ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा दी है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लिमिट 3 से 5 लाख रुपये तय कर दी है।

वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि एग्रीकलचर, एसएमई और एक्सपोर्ट सहित हमारा फोकस ग्रोथ के 4 इंजन पर रहा है। एग्रीकल्चर हमारे लिए पहला इंजन है। इसके लिए मैं कुछ खास ऐलान करने जा रही हूं। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने कहा, 'किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। इसमें क्रॉप डायवर्सिफिकेशन पर फोकस होगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिसका लाभ 7.5 करोड़ किसानों को होगा। ❑❑

https://www.jagran.com/business/budget-union-budget-2025-26-union-finance-minister-nirmala-sitharaman-announces-for-farmers-increase-credit-card-limit-23876652.html

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठक

सचित्र झलक

महाकुंभ, प्रयागराज

स्वदेशी मेला, हुबली, कर्नाटक

पश्चिम उड़ीसा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 फरवरी 2025
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

अभियान बैठक

सचित्र झलक

हुगली, मध्य बंग प्रांत

उत्तर पश्चिम बंगाल

कोल्लम, केरल

दक्षिण वेस्ट बंगाल

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती